घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 72- रविवार 11- जनवरी 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

संक्षिप्त समाचार

अयोध्या के राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश..

परिसर में घुसे 3 लोग पकड़े गए...

अयोध्या,10 जनवरी 2026। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में शनिवार सुबह 3 लोग घुस गए और नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगे। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उन्हें रोका और हिरासत में ले लिया। पकड़े गए लोगों में 1 युवक,एक 56 साल का व्यक्ति और 1 युवती शामिल है। इन लोगों ने खुद को कश्मीर का रहने वाला बताया है। अभी तक किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि आरोपी कौन हैं और कहां के रहने वाले हैं? प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार,तीनों संदिग्ध हरकतें कर रहे थे। तीनों से राम मंदिर परिसर में बने पुलिस कंट्रोल रूम में पूछताछ की जा रही है कि वो अयोध्या क्यों आए थे? तीनों राम मंदिर के गेट डी1 से घुसे। इसके बाद सीता रसोई के पास अबू अहमद शेख नमाज पढ़ने के लिए बैठ गया। पुलिसवालों ने उसे उसे ऐसा करते देखते ही हिरासत में ले लिया। वह कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है। वहीं, पकड़ी गई लड़की नाम सोफिया है। दूसरे युवक का नाम अभी पता नहीं चल पाया है। दरअसल,राम मंदिर में एंट्री करने के दौरान सिर्फ चेकिंग होती है। आधार कार्ड या किसी अन्य परिचय पत्र को चेक नहीं किया जाता। इसी का फायदा उठाकर तीनों राम मंदिर परिसर में एंट्री कर गए। इसके बाद तीनों सीता रसोई तक जा पहुंचे, जो मुख्य मंदिर से सिर्फ 200 मीटर दूर है। यहां नमाज पढ़ने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों ने जब उन लोगों को रोका, तो उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं, घटना की सूचना मिलते ही खुफिया एजेंसियां, स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी सक्रिय हो गए हैं। हालांकि,इस मामले पर जिला प्रशासन ने फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने भी पूरे प्रकरण पर चुप्पी साध रखी है।

भारत प्रकाशन उद्योग में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र : धर्मेंद्र प्रधान

नई दिल्ली,10 जनवरी 2026। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि भारत प्रकाशन उद्योग में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। डिजिटल युग में किताबें मानव की सबसे बड़ी मित्र हैं और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला ज्ञान, विचार और संस्कृति का महाकुंभ बन गया है। प्रधान ने यहां के भारत मंडपम में 10 से 18 जनवरी तक चलने वाले 53वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मेले में 35 से अधिक देशों के 1,000 से ज्यादा प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही 3,000 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं और 600 से ज्यादा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह पहली बार है जब विश्व पुस्तक मेले में आम जनता के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है, जिससे लाखों पाठक, छात्र और परिवार बिना किसी शुल्क के मेले में भाग ले सकेंगे। शिक्षा मंत्री प्रधान ने बताया कि इस वर्ष मेले की थीम भारतीय सैन्य इतिहास-शौर्य एवं प्रज्ञा @75 रखी गई है। यह थीम स्वतंत्रता के 75 वर्षों में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साहस,बलिदान और राष्ट्र निर्माण में योगदान को समर्पित है।

पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में महाआरती की

ऊं जाप भी किया, यहां सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा,पीएम 3 दिन के गुजरात दौरे पर

सोमनाथ,10 जनवरी 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 जनवरी तक 3 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। शनिवार शाम वे राजकोट से हेलिकॉप्टर के जरिए सोमनाथ पहुंचे। यहां उन्होंने रोड शो किया। इसके बाद सोमनाथ मंदिर पहुंचे। सोमेश्वर महादेव की महाआरती की। इसके बाद 72 घंटे चलने वाले ऊं जाप में शामिल होकर ऊं जाप भी किया। अब पीएम सोमनाथ सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। रोड शो के दौरान पीएम को देखने के लिए सड़क के दोनों और भीड़ मौजूद रही थी। मंदिर पहुंचने से पहले पीएम ने सोमनाथ सर्किट हाउस में सोमनाथ के ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग भी की थी। अब सोमनाथ में कुछ देर बाद ड्रोन शो होगा,जिसके जरिए सोमनाथ गाथा प्रस्तुत की जाएगी। शो के लिए 3 हजार ड्रोन शामिल किए गए हैं। दरअसल पीएम मोदी ने सोमनाथ पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के हजार साल पूरे होने पर हो रहे इस कार्यक्रम को 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' नाम दिया है। पर्व 8 से 11 जनवरी तक मनाया जा रहा है।

आज का कार्यक्रम

पीएम मोदी आज सुबह करीब 9:45 बजे शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। करीब 2 किमी लंबी इस यात्रा में 108 घोड़े नजर आएंगे। शौर्य यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निकाली जाती है। यात्रा का समापन सोमनाथ के सद्भावना मैदान में होगा। इसके बाद पीएम सोमनाथ मंदिर में दर्शन,जलाभिषेक और पूजा अर्चना करेंगे। सुबह लगभग 11 बजे सोमनाथ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और सद्भावना मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

सद्भावना मैदान 14 साल पहले किया था उपवास

वर्ष 2012 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे,तब उन्होंने सोमनाथ के इसी मैदान में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ाने के मुद्दे पर हुए जन आंदोलन के दौरान सद्भावना उपवास रखा था। तब से यह मैदान 'सद्भावना मैदान' के नाम से पहचाना जाने लगा है।

ओडिशा के राउरकेला में बड़ा विमान हादसा

लैंडिंग के दौरान रनवे पर पलटा प्लेन,6 घायल

नई दिल्ली,10 जनवरी 2026। ओडिशा के स्टील सिटी कहे जाने वाले राउरकेला से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के स्थानीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद 'इंडिया वन एयर' का एक 9-सीटर छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मिली जानकारी के अनुसार, यह विमान राउरकेला से राज्य की राजधानी भुवनेश्वर की ओर जा रहा था। विमान ने जैसे ही रनवे से हवा में उड़ान भरी, तकनीकी खराबी या अन्य अज्ञात कारणों से वह असंतुलित होकर क्रैश हो गया। इस घटना के बाद हवाई अड्डे और आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया और तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिए गए। हादसे के समय विमान में कुल 7 लोग सवार थे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इसमें 6 यात्री अपनी मंजिल की ओर यात्रा कर रहे थे, जबकि 1 पायलट विमान का संचालन कर रहा था। राहत की

बात यह रही कि विमान के क्रैश होने के बावजूद शुरुआती रिपोर्टों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है, हालांकि कुछ लोगों को मामूली चोटें आने की बात कही जा रही है। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी यात्रियों और पायलट को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और उनकी चिकित्सकीय जांच की गई। छोटे विमानों में इस तरह के हादसे अक्सर बड़ी जानलेवा त्रासदी का रूप ले लेते हैं, लेकिन इस मामले में एक बड़ी अनहोनी टल गई।

जंग दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए लड़ते हैं हम मनोरोगी नहीं कि शव देखकर खुशी मिले : डोभाल

नई दिल्ली,10 जनवरी 2026। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शनिवार को कहा कि युद्ध राष्ट्र की इच्छाशक्ति के लिए लड़े जाते हैं। उन्होंने कहा,'हम साइकोपैथ (मनोरोगी) नहीं हैं, जिन्हें दुश्मन के शव या कटे हुए अंग देखकर संतोष या सुकून मिले। लड़ाइयां इसके लिए नहीं लड़ी जाती। उन्होंने कहा कि युद्ध किसी देश का मनोबल तोड़ने के लिए लड़े जाते हैं, ताकि वह हमारी शर्तों पर आत्मसमर्पण करें और हम अपने लक्ष्य हासिल कर सकें। अजीत डोभाल ने शनिवार को नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन समारोह के दौरान ये बाते कहीं। उन्होंने युवाओं से कहा कि आप

अपनी इच्छाशक्ति बढ़ा सकते हैं। वही इच्छाशक्ति राष्ट्रीय शक्ति बन जाती है। दुनिया में हो रहे सभी युद्ध और संघर्षों को देखें तो साफ है कि कुछ देश दूसरों पर अपनी इच्छा थोपना चाहते हैं। इसके लिए अपनी ताकत का प्रयोग कर रहे हैं। अगर कोई देश इतना शक्तिशाली है कि कोई उसका विरोध न कर सके तो वह हमेशा स्वतंत्र रहेगा। लेकिन अगर संसाधन और हथियार हों, पर मनोबल न हो तो सब कुछ बेकार हो जाता है। मनोबल बनाए रखने के लिए लीडरशिप जरूरी होती है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में ऐसा नेतृत्व है। एक ऐसा लीडर जिसने 10 सालों में देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज का स्वतंत्र भारत हमेशा से उतना स्वतंत्र नहीं था। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बड़े बलिदान दिए। अपमान झेला और बेबसी के दौर से गुजरे। कई लोगों को फांसी हुई। हमारे गांव जलाए गए। हमारी सभ्यता को नुकसान पहुंचाया गया। यह इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि आज भारत के हर युवा के अंदर एक आग होनी चाहिए। 'बदला' शब्द शायद बहुत अच्छा न लगे, लेकिन बदला खुद एक ताकतवर एहसास है। हमें अपने इतिहास का बदला लेना है। हमें इस देश को उस मुकाम पर वापस ले जाना है, जहां हम अपने अधिकारों, अपने विचारों और अपने विश्वास के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद पहली बार पैतृक गांव पहुंचे सूर्यकांत

बोले-10वीं में अच्छे रिजल्ट के लिए स्कूल में सोते,मास्टरजी रात तक पढ़ाते थे

नई दिल्ली,10 जनवरी 2026। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के हरियाणा दौरे के दूसरे दिन खुली जीप में सवार होकर हांसी जिले में अपने पैतृक गांव पेटवाड़ पहुंचे। यहां उनके सम्मान में एक समारोह रखा गया था। उनके साथ कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। यहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा... 'मुझे अपने इंग्लिश के टीचर मदनखेड़ी गांव निवासी मास्टर प्रेम सिंह जी आज भी याद हैं। उन्होंने कुछ बच्चों को चुना ताकि मैट्रिक (10वीं) एग्जाम में गांव का रिजल्ट अच्छा आए। हम धान की पराली बिछाकर स्कूल के बड़े कमरे में सोते थे और रात 11-12 बजे तक मास्टर जी हमें पढ़ाते थे। यह केवल पढ़ाई नहीं थी, यह एक मां-बाप जैसी तपस्या थी। ' इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को

हिसार स्थित अपने पुराने कॉलेज गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में एलुमनी मीट में पहुंचना था। हालांकि,लेट होने के कारण वह नहीं आ पाए। एलुमनी मीट में जननायक जनता पार्टी सुप्रीमो डॉ. अजय चौटाला,पूर्व मंत्री संपत सिंह समेत उनके 12 क्लासमेट और 2 टीचर को भी न्योता दिया गया था। शनिवार सुबह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिसार के बरवाला पहुंचे। यहां उन्होंने नवस्थापित एसडीजेएम कोर्ट का उद्घाटन और न्यायिक परिसर का शिलान्यास किया। उनका स्वागत करने कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा और रणबीर गंगवा पहुंचे। यहां अपने संबोधन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा...'ज्यूडिशिरी कोर्ट कॉम्प्लेक्स की इमारतें तो बन जाएंगी,मगर यह तभी कामयाब होंगी,जब न्याय का खून इनमें दौड़े और इनमें गरीब का दर्द समझने की क्षमता हो।' इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नारनौंद पहुंचे। यहां भी कोर्ट परिसर का उद्घाटन किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हिसार स्थित अपने पुराने कॉलेज गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में एलुमनी मीट में पहुंचना था। हालांकि, लेट होने के कारण वह नहीं आ पाए।

'चुनाव आते ही ईडी को याद आते हैं दस्तावेज',कपिल सिब्बल बोले...विपक्ष को डराने का औजार बनी एजेंसी

नई दिल्ली,10 जनवरी 2026। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई को लेकर राज्य से लेकर देशभर की राजनीति में गर्माहट तेज है। इसी बीच इस कार्रवाई को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही जांच एजेंसियों को अचानक दस्तावेजों की याद आ जाती है और इसका मकसद सिर्फ विपक्षी नेताओं को परेशान करना होता है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सिब्बल ने पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जहां भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती, वहां ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को परेशान करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

केसी त्यागी की जेडीयू से छुट्टी! पार्टी ने किया किनारा कहा...हमारा उनसे आधिकारिक संबंध नहीं

नई दिल्ली,10 जनवरी 2026। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग करने वाले पूर्व सांसद केसी त्यागी से जनता दल यूनाइटेड ने खुद को अलग कर लिया है। जदयू का कहना है कि त्यागी के हालिया बयान पार्टी की आधिकारिक राय नहीं हैं और उनसे संगठन का कोई औपचारिक संबंध नहीं है। केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नीतीश कुमार को समाजवादी आंदोलन का अनमोल रत्न बताते हुए उन्हें भारत रत्न देने की मांग की थी। उन्होंने अपने पत्र में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर का भी उल्लेख किया था,जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इससे पहले भी कुछ नेताओं की ओर से नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठती रही है, लेकिन तब जदयू की तरफ से कोई

सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने शनिवार को स्पष्ट कहा कि केसी त्यागी के हालिया बयान निजी हैं और पार्टी के आधिकारिक स्टैंड को नहीं दर्शाते। उन्होंने कहा कि त्यागी अपने वक्तव्य व्यक्तिगत हैसियत में दे रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी यह स्पष्ट नहीं है कि वे फिलहाल जदयू में किसी भूमिका में हैं या नहीं। इसलिए उनके बयानों को जदयू से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

माहेश्वरी समाज जॉब सीकर नहीं रहा,जॉब क्रिएटर रहा,समाज के दिए हुए भामाशाहों की सूची बनाएंगे तो कई पेज भर जाएंगे : अमित शाह

जोधपुर,10 जनवरी 2026। जोधपुर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा- माहेश्वरी समाज जॉब सीकर नहीं रहा, जॉब क्रिएटर रहा है। ऐसे ही सदियों तक यह समाज देश की सेवा करता रहे। राम मंदिर पर पुस्तक लिख रहा युवक मेरे पास आया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास क्या जानकारी है? उसने बताया कि आजादी के बाद राम मंदिर के लिए सबसे पहले प्राणों की आहूति देने वाले दोनों भाई माहेश्वरी समाज से थे। अमित शाह ने कहा कि देश के सांस्कृति पुनर्जागरण में भी माहेश्वरी समाज का योगदान बहुत बड़ा है। माहेश्वरी समाज के हाथ में तलवार भी अच्छी लगती है, तराजू भी। समाज के दिए हुए भामाशाहों की सूची बनाएंगे तो कई पेज भर जाएंगे। शनिवार को शाह पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में चल रहे माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा- देश को हर क्षेत्र में सर्वप्रथम लाने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं, जिन्हें माहेश्वरी समाज कर सकता है। पहली, जो उत्पादन करते हैं तो वो करिए, लेकिन साथ में ऐसी चीजों का उत्पादन भी

करें, जो भारत में नहीं बनती है। दूसरी, स्वदेशी। जितना हो सके, उतना स्वदेशी चीजों का उपयोग करें। यह तय कर लें कि मेरे देश में बनी है, उसी चीज का व्यापार करूंगा। स्वदेशी के साथ स्वभाषा का भी उपयोग करें। जब मुगलों के साथ लड़ते थे तो राजा-महाराजा के खजाने भरने का काम माहेश्वरी समाज ने किया। जब अंग्रेजों से लड़े तो महात्मा गांधी की लड़ाई का खर्च माहेश्वरी समाज के सेठों ने उठाया है।

जहां न पहुंचे रेलगाड़ी,वहां पहुंच जाए मारवाड़ी

अमित शाह ने कहा कि चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी को अपनाना हो, माहेश्वरी समाज ने प्रगतिशील समाज का परिचय दिया है। हमारे गुजरात में कहावत है कि जहां न पहुंचे रेलगाड़ी, वहां पहुंच जाए मारवाड़ी। अमित शाह ने कहा कि जब समाज के आयोजन होते हैं तो कई प्रगतिशील लोग टीका-टिप्पणी करते हैं, मैंने ऐसी कई टिप्पणी झेली है। हमारे यहां समाजों के ऐसे महाकुंभ भारत को मजबूत करते हैं, भारत को विघटित नहीं करते। यदि हर समाज अपने गरीब भाई-बहनों की देखभाल स्वयं कर ले तो भारत से गरीबी मिट जाए। यदि हर समाज आत्मनिर्भर बन जाए तो पूरा भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा।

जयपुर में 9000 नव नियुक्त कॉन्स्टेबलों को अमित शाह ने सौंपे नियुक्ति पत्र,बोले...योग्यता से मिली नौकरी,सिफारिश नहीं

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित भव्य समारोह में 9000 नव नियुक्त कॉन्स्टेबलों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत 'राम-राम' से करते हुए कहा कि आज जिन 9000 युवाओं को नियुक्ति मिली है, वह किसी सिफारिश से नहीं बल्कि पूरी तरह योग्यता और पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर मिली है। उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य तभी प्रगति कर सकता है, जब वहां नियुक्तियां निष्पक्ष और पारदर्शिता से हों। अमित शाह ने कहा कि राजस्थान में वर्तमान सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को भरोसेमंद बनाया है और पेपर लीक जैसी समस्याओं से युवाओं को निजात दिलाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सराहना करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय चले आ रहे पेपर लीक के सिलसिले को समाप्त कर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया गया है। शाह ने कहा कि मेहनत और ईमानदारी से चयनित पुलिसकर्मी ही कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय

गृह मंत्री ने रतन नगर पुलिस थाना को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना का पुरस्कार मिलने का उल्लेख करते हुए राजस्थान पुलिस के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रशिक्षण, अनुशासन और ईमानदारी के साथ राजस्थान पुलिस देश के लिए एक आदर्श बन रही है। कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्री, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में नव नियुक्त कॉन्स्टेबल उपस्थित रहे।

संपादकीय

अनंत संभावनाओं को समेटे है हिंदी

विश्वभाषा बनने की ओर अग्रसर...

विश्व हिंदी दिवस हिंदी के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य,वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर विचार का अवसर है। इस वर्ष प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं,जिसने वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार-प्रसार की नींव रखी। भारत की आर्थिक प्रगति,भूमंडलीकरण और मनोरंजन उद्योग ने हिंदी को विश्वभाषा बनने की ओर अग्रसर किया है। तकनीक के साथ मिलकर हिंदी अपनी अंतरराष्ट्रीय क्षमता बढ़ा रही है...

दस जनवरी का दिन 'विश्व हिंदी दिवस' के रूप में हिंदी प्रेमियों को उत्साह से भर देता है। यह दिन हमें हिंदी भाषा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य,उसकी वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर विचार-मंथन का अवसर भी प्रदान करता है। इस वर्ष 'विश्व हिंदी दिवस' हमारे लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन को पचास वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 1975 में नागपुर में 10 जनवरी को आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार-प्रसार का महत्वपूर्ण प्रयास था,जिसका उद्घोष था-'वसुधैव कुटुंबकम्'।30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने उसमें सहभागिता की थी। उस सम्मेलन ने भारत और भारत के बाहर बसे भारतीयों में अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की उत्कंठा जगा दी। उनमें केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर भी हिंदी के प्रचार-प्रसार से जुड़ने का संकल्प जागृत हुआ। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं,बल्कि वैश्विक आवश्यकता की दृष्टि से भी हिंदी का महत्व रहा है। अनेक विदेशी विद्वानों ने भी हिंदी की सेवा की है। इस दृष्टि से बेल्जियम के फादर कामिल बुल्के, मारीशस के अभिमन्यु अनंत,जापान के प्रो. क्यूया दोई,जर्मनी के लोथार लुत्से, मास्को के येवगेनी पेत्रोविच चेलिशेव,श्रीलंका की इंद्रा दसनायक,न्यूजीलैंड के रोनाल्ड स्टुअर्ट मैकग्रेगर तथा हंगरी के इमरै बंधा आदि के नाम गिनाए जा सकते हैं। भाषा किसी भी देश की संस्कृति की मूल्यवान उपलब्धि होती है। वह हमारे भावबोध और आत्मबोध का ऐसा हिस्सा होती है,जिसे यदि हमसे काटकर अलग कर दिया जाए तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। हर भाषा उसे बोलने वालों के इर्द-गिर्द एक जादुई घेरा खींच देती है। यह जादुई घेरा वस्तुतः भाषा की परिधि ही है, जिसके भीतर हमारी पहचान सुरक्षित रहती है, क्योंकि भाषा किसी समूह के सांस्कृतिक प्रतीक-रूपों में जीवित रहती है। आज हिंदी की वैश्विक उपस्थिति ने सिद्ध कर दिया है कि शब्द-सृष्टि का व्यापार अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण है।विश्व स्तर पर हिंदी की मांग के नए व्यावसायिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ उभर रहे हैं। विश्वभर में बसे भारतीय हिंदी के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। वे यह भली-भांति जानते हैं कि हर भाषा की संरचना के सामाजिक-सांस्कृतिक स्रोत होते हैं। इसीलिए भाषा हमें अपने इतिहास,मिथक और परंपरा से जोड़ती है। यह जुड़ाव ही सामूहिक अस्मिता बनकर अत्यंत मूल्यवान हो जाता है। इस प्रकार हिंदी का विश्वबोध निर्मित हो रहा है। भारत की तेज आर्थिक प्रगति को देखकर भाषाशास्त्रियों का अनुमान है कि आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपर्क की जो दस भाषाएं होंगी, उनमें हिंदी भी शामिल रहेगी। वह ज्ञान-विज्ञान,उच्च प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के वैश्विक परिदृश्य में अपने सामर्थ्य को सिद्ध करेगी। भूमंडलीकरण से जन्मी परिस्थितियों ने भी विश्व भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति को सुदृढ़ किया है। उपभोक्तावादी संस्कृति में भाषा की शक्ति और सामर्थ्य का मानक बाजार बन गया है। आज भाषा समृद्धि के मानदंडों से नियंत्रण और निर्धारण के खेल को स्वीकार या अस्वीकार करती है। भारत के बदलते सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारतीयता को अपनी मार्केटिंग का प्रभावी हथियार बनाकर अपने उत्पादों के प्रचार-प्रसार की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने भारतीय आस्थाओं,परंपराओं और छवियों को विज्ञापनों में जागृत करना शुरू कर दिया है। इन दिनों विज्ञापनों में भारतीय सांस्कृतिक प्रतीकों का व्यापक उपयोग हो रहा है। विज्ञापन निर्माता हिंदी तथा भारतीय भाषाओं का प्रयोग कर भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान को जागृत कर रहे हैं। मनोरंजन उद्योग ने भी हिंदी के वैश्विक क्षितिज को अभूतपूर्व विस्तार दिया है। हिंदी फिल्मों के माध्यम से हिंदी दुनिया भर के देशों में फैल रही है।

हर भाषा अपने युग की परिस्थितियों और प्रेरणाओं के अनुसार बदलती है। आज 'तकनीकी वर्चस्व' के युग में तकनीक हिंदी को नयापन दे रही है। क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों और बोलचाल के शब्दों से हिंदी का नया स्वरूप भी सामने आ रहा है। ऐसे ही विकास के कई मोड़ों से गुजरकर हिंदी अपनी अंतरराष्ट्रीय क्षमता की पहचान बना रही है। हिंदी की अंतरराष्ट्रीय क्षमता का विकास बाजार की जरूरतों से बने विश्वग्राम और विश्व-मानव की मांग भी है। राजभाषा, संपर्क भाषा और जनभाषा के सोपानों को पार कर हिंदी विश्वभाषा बनने की ओर अग्रसर है।

हिंदी को उजाड़ रहें हैं परिवारवाद

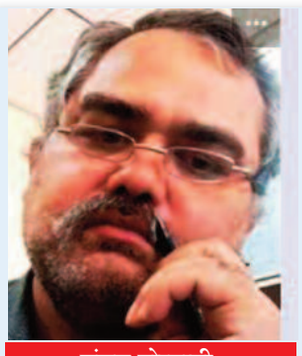

संजय गोस्वामी,
दुंदी बाजार,पटना बिहार

आज हिंदी दम तोड़ते नजर आ रही है क्योंकि उसमें भविष्य बिल्कुल सही नहीं लग रहा है जिसमें क्षेत्र की भाषा भी कहीं ना कहीं हिंदी पर हावी हो रही है और ऐ वोट लेने का भी अच्छा माध्यम हो गया है। आखिर बंगाल और दक्षिण क्षेत्र में हिंदी में लोग बोलना क्यों नहीं पसन्द करते है। हिंदी की पत्रिका जो सरकारी तर्ज पर आती है अधिकांश में परिवारवाद घुस गया है बस एक उनका गुट है जो परिवार जैसा है उसी का लेख छपता है लेकिन प्राइवेट पत्रिका में ऐसा नहीं होता क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो मार्केट में पीट जाएगी और इसलिए उसमें लेखकों का अच्छा लेख होता है क्योंकि मार्केट में रन करने के लिए उसे हर लेख की गुणवत्ता बनानी होती है इसलिए उसमें एक्सपर्ट पैनल होता है और लेख उसी के छपते हैं जो एक्सपर्ट होते है। ऐसे में नवीन लेखकों को जगह मिलना मुश्किल हो जाता है लेकिन सरकारी पत्रिका में पहले नवलेखकों को जगह मिलती थी कहीं नहीं तो पाठकीय प्रतिक्रिया में तो मिल ही जाती थी विज्ञान प्रगति जो पहले हर बुक स्टाल में मिलती थी आज कुछ ही छप रही है क्योंकि सरकार ने देखा होगा कि इसमें जो छात्रों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। अतः डिजिटल दौड़ में ऑनलाइन और कुछ प्रिंट कर मिलती है आज हिंदी विश्व के परिपेक्ष हिंदी का मुख्य केंद्र,मौरीशस में विश्व हिंदी सचिवालय है लेकिन उसमें लोग विश्व हिंदी सेमिनार तो कराते है लेकिन जो हिंदी के विकास हेतु वहाँ जाते हैं वो वहाँ जहाँ तहाँ घूमते और फोटो खिचवाने में लगे रहते हैं आखिर हिंदी को घूमने फिरने और अपने लेख व्यक्तिगत संपर्क से छपवाना और मानदेय लेना कहाँ तक उचित है हिंदी में विज्ञान को प्रसारित करने वाली संस्थान जो 1935 में विज्ञान परिषद प्रयाग बनी उसका आज हाल इतना बुरा है कि उसके ऑफिस को ईलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने प्रक्रिया से अपने पास ले ली आपसी विवाद होते हैं लेकिन ऐ निर्णय हिंदी में विज्ञान के भविष्य को लेकर लेनी चाहिए अतः अब एक मात्र हिंदी को विज्ञान में प्रसार करनेवाली हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद मुंबई दिख रही है जिसने अब तक वैज्ञानिक पत्रिका का नियमित प्रकाशन लगभग 58 सालों से करती आ रही है क्योंकि विज्ञान प्रसार जो हिंदी में विज्ञान का प्रसार साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत करती थी वो भी पिछले साल बन्द हो गईं। यानी कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। पब्लिक तक ऐ

संदेश नहीं गया और जब किसी को किसी के बारे में सालों से पता नहीं रहता तो सरकार उसके काम पर नाराज होकर ही अपनी कदम आगे बढ़ाती है। सरकार को ये समझ में आ गया कि ये संस्थान में काम ठीक नहीं हो रहा है इसलिए उस पर तर्ज करना उचित नहीं है क्योंकि जब बजट माँगा जाता है तो फिजिकल एक्टिविटी देखी जाती है और ये देखा जाता है कि अनुमानित बजट में फाइनेंस और फिजिकल दोनों ठीक है तभी वो फंड मिलता है कहीं ना कहीं हिंदी विज्ञान को जनमानस तक पहुंचाने में सफलता नहीं मिली और जब बजट ही बन्द हुआ तो कहानी ही खत्म हो गई लेकिन कुछ गैर सरकारी संस्थान अभी भी हिंदी में विज्ञान में रूचि पैदा करने के हेतु छात्रों के एक बड़ा वर्ग को फायदा दिया है। इसलिए आप बुक स्टाल पर अधिकतर हिंदी के मैगजीन गैरसरकारी संस्थान के द्वारा ही पाते हैं कागज की गुणवत्ता भले ही खराब हो लेकिन अंदर सामग्री काम की रहती है तभी चल रही है इसलिए अब काम निःस्वार्थ भाव से होगा तभी आगे बढ़ सकते हैं हिन्दी की विज्ञान संबंधी पत्रिका वैज्ञानिक (त्रैमासिक) पिछले 53 साल कई शिक्षाविदों और वैज्ञानिक पत्रिका हिन्दी के माध्यम से विज्ञान संचार में प्रयासरत हैं। वैज्ञानिक वर्ष में चार अंक द्वारा हिन्दी में गांव शहरों में वैज्ञानिक चिंतन प्रारंभ करने के उद्देश्य से पत्रिका पाठकों के लिए उपलब्ध है। एक उच्चस्तरीय लेखों का नियमित संकलन हिन्दी में विज्ञान में वैज्ञानिकों शिक्षाविदों,संस्थानों के छात्रों व आप पाठक को मिले एवं एक वैज्ञानिक जागरूक मंच पैदा करना पत्रिका का प्रेरणा स्रोत रहा है। पत्रिका के मुख्य उद्देश्य विज्ञान संबंधी प्रसार जानकारी के लिए है और जनता के बीच नई प्रौद्योगिकियों, आविष्कार,नवाचारों में जागरूकता पैदा करने में और छात्रों, वैज्ञानिकों,तकनीशियनों के बीच आविष्कार शीलता,नवीनता और उद्यम शीलता की भावना को बढ़ावा देना है।वर्तमान में विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, बायोलॉजी कृषि विज्ञान,प्राचीनतम तथा मूल चिकित्सा-प्रणाली,नैनोटे क्नोलॉजी, पर्यावरण नाभिकीय विज्ञान, व प्रौद्योगिकी,आविष्कार,परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण अनुप्रयोग,नवाचारों से संबंधित राष्ट्रीय महत्व आदि के विषयों पर केंद्रित रहा है। विज्ञान को हिंदी में जनमानस तक पहुंचाने के लिए हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद्,बार्क,मुंबई द्वारा प्रकाशित'वैज्ञानिक'भी निरंतर प्रयासरत हैं । वैज्ञानिक का परिचय अंक लगभग 53 वर्ष पूर्व 1969 में प्रकाशित हुआ था। वैज्ञानिक चिंतन हिन्दी में उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इसमें नवीनतम शोध की जानकारी हिन्दी में पाठकों तक पहुंचाई जाती है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य आम पाठक में राजभाषा में वैज्ञानिक लेख लिखने की क्षमता पैदा करना,नये शोध की जानकारी एक दूसरे तक पहुंचाना है। वर्ष 2016 में इसने इंसान की सभी निष्ठावान सदस्यों के प्रयास से प्राप्त किया है। कुछ विशेषांक अंक भी निकले जिससे छात्र, वैज्ञानिक,विज्ञान शिक्षक,पाठक लाभान्वित हुयें। स्तंभ विज्ञान समाचार विज्ञान दिवस-पर प्रकाशित कर वैज्ञानिक में विज्ञान के स्कूली बच्चों, के नए ज्ञान के लिए भी है। 'वैज्ञानिक' द्वारा पाठकों में हिन्दी में वैज्ञानिक जागरूकता पैदा की जाती है जिसमें विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों को समझाया जाता है ताकि लेख के स्तर पर पाठक अपने ज्ञान व क्षमता में वृद्धि कर सके इस अंक में प्रकाशित हुये विज्ञान लेख जैसे खेती, स्वच्छता, में किट पशुपालन,कोविड-19, एनर्जी, परमाणु ऊर्जा,वैज्ञानिक डा ए.पी.जे. अब्दुल कलाम,डॉ आर चिदंबरम स्मृति विशेष आदि पर विभिन्न प्रकार के शोधकर्ताओं व विज्ञान लेखकों द्वारा लिखा गया लेख वैज्ञानिक बिषयो के उपर हिन्दी में लेख लिखने की प्रेरणा देता है.पत्रिका के मुख्य संपादक डॉ ब्रजेश कुमार सिन्हा, संपादकीय बोर्ड के सदस्य सर्वश्री राजेश कुमार मिश्र, राजेश कुमार,शेर सिंह मीणा,डॉ संजय कुमार पाठक व वैज्ञानिक के व्यवस्थापक,सर्वश्री श्री नवीन त्रिपाठी, बी.एन. मिश्र,अनिल अहिरवार, प्रकाश कश्यप,राज कुमार डाबरा बधाई के पात्र हैं,आशा है की आने वाले समय में हिंदी में और भी अच्छे कार्य हो तथा इसमें भी भेदभाव के बिना मेरिट आधारित लेख का चुनाव व पुरस्कार व पुस्तक प्रकाशित हो।

मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया

डॉ. मुश्ताक़ अहमद शाह सहज़
हरदा,मध्य प्रदेश

मशहूर शायर साहिर लुधियानवी के गीत की ये पंक्तियाँ,,
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया
हर फिक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया।
जो मिल गया उसी को मुक़द्दर समझ लिया
जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया।

जीवन की एक गहरी सच्चाई को बयान करती हैं। ये शेर हमें सिखाता है कि ज़िंदगी एक लंबी यात्रा है,जिसमें हम हर मोड़ पर जो कुछ पाते हैं,उसे ही अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेते हैं। ये भाव न सिर्फ़ कविता का हिस्सा है,बल्कि रोज़मर्रा की जिंदगी का सार भी है। आज के भागदौड़ भरे दौर में,जब हर कोई परफ़ेक्ट लाइफ़ की तलाश में भटक रहा है, ये पंक्तियाँ हमें वर्तमान में जीने की सीख देती हैं। जिंदगी का साथ निभाना,स्वीकार्यता की ताक़त जिंदगी हमें कभी वैसा नहीं देती जैसा हम सपने बुनते हैं। कभी अपनों का साथ मिलता है, तो कभी अकेलापन,कभी कामयाबी का स्वाद चखाते हैं, तो कभी नाकामी का कड़वा घूंट। लेकिन सच्ची हिम्मत तो इस सबको निभाने में है। जिंदगी का साथ निभाता चला गया यानी हर उतार-चढ़ाव को बिना शिकायत के अपनाना। सोचिए,एक किसान जो बारिश न हो तो भी बीज बोता रहता है, या एक माँ जो बीमार बच्चे की सेवा में रात-दिन एक कर देती है। ये लोग मुकद्दर को कोसते नहीं, बल्कि जो मिला है उसी में खुशियाँ तलाश लेते हैं। आज की पीढ़ी सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती ज़िंदगियाँ देखकर अपनी परेशान होती है,लेकिन असली सुकून तो वही है जो मिला है, उसे पूरा निभाने में मिलता है। मनोविज्ञान में इसे ग्रेटिट्यूड कहते हैं जो मिला है,उसके लिए शुक्रगुज़ार होना। ये भाव हमें तनाव से मुक्ति देता है और जीवन को सरल बनाता है। जो मिला, उसी को मुकद्दर समझना,व्यावहारिक सबक जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया ये पंक्ति भाग्यवाद नहीं, बल्कि व्यावहारिक दृष्टिकोण सिखाती है। जिंदगी में रिश्ते, नौकरी, स्वास्थ्य सब कुछ परिवर्तनशील है। हमेशा बेहतर की चाह में वर्तमान को खो देते हैं। उदाहरण लीजिए, एक नौकरी जो पसंद न हो,लेकिन परिवार चलाने वाली होती है,और इसे मुकद्दर मानकर निभाइए,तो नई संभावनाएँ खुद खुलेंगी। भारतीय संस्कृति में भी ये भाव गहरा है। भगवद्गीता का कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यही कहता है,कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आधुनिक उदाहरण,असफलता के बाद भी हार न मानना और जो मिला,उसी को निभाना। आम आदमी के लिए ये मतलब है,छोटी-छोटी खुशियों को अपनाना। अगर साथी वैसा न हो जैसा सोचा,तो जो है उसी में प्यार ढूंढो,अगर कम कमाई हो,तो उसी में संतोष रखो। इससे न केवल मन शांत रहता है,बल्कि रिश्ते मज़बूत होते हैं। आज के दौर में इस भाव का महत्व,आज महंगाई,बेरोज़गारी और रिश्तों की जटिलताओं के बीच ये शेर एक मंत्र की तरह काम करता है। युवा डिप्रेशन से जूझ रहे हैं क्योंकि परफ़ेक्ट की दौड़ में हैं। लेकिन जो मिला है,उसे निभाने से आत्मविश्वास बढ़ता है।

कविता

हिंदी मेरे उर बसे

डॉ प्रियंका सौरभ
आर्यनगर,
हिसार
(हरियाणा)

आन-बान सब शान है,और हमारा गर्व।
हिंदी से ही पर्व है,हिंदी सौरभ सर्व।।
हिंदी हृदय गान है,मृदु गुणों की खान।
आखर-आखर प्रेम है,शब्द-शब्द है ज्ञान।।
बिंदिया भारत भाल की,हिंदी एक पहचान।
सैर कराती विश्व की,बने किताबी यान।।
प्रीत प्रेम की भूमि है,हिंदी निज अभिमान।
मिला कहाँ किसको कहीं,बिन भाषा सम्मान।।
वन्दन,अभिनन्दन करे,ऐसा हो गुणगान।
ग्रंथन हिंदी का कर लो,तभी मिले सम्मान।।
हिंदी भाषा रस भरी,रखती अलग पहचान।
हिंदी वेद पुराण है,हिंदी हिन्दुस्तान।।
हिंदी की मैं दास हूँ,करूँ मैं इसकी बात।
हिंदी मेरे उर बसे,हिंदी हो जज्बात ।।
निज भाषा का धनी जो,वही सही धनवान।
अपनी भाषा सीख कर,बनता व्यक्ति महान।।
मौसम बदले रंग जब,तब बदले परिवेश।
हो हिंदीमय स्वयं जब,तभी बदलता देश।।
निज भाषा बिन ज्ञान का,होता कब उत्थान।
अपनी भाषा में रचे,सौरभ छंद सुजान।।
एक दिवस में क्यों बंधे,हिन्दी का अभियान।
रचे बसे हर पल रहे,हिन्दी हिन्दुस्तान।।

माटी हमर धरोहर

अशोक पटेल आशु
तुस्मा,
शिवरीनारायन
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के पावन भूईया,
जेमा देव-धामी के डेरा हे
महामाई जिहाँ शीतला बिराजे,
जेमा ठाकुर-देवा के बसेरा हे।
दया-धर्म,कला-संस्कृति के,
जिहाँ राम-कथा के चौरा हे,
अइसे जिहाँ देवी-दाई बिराजे
जेकर सेवा म जवांरा-पचरा हे।
इही भुईंया हर तीरथ बरोबर
इहिच म बसे चारो धाम हे
इहें बहे पुण्य पतीत-पावनी
दाई चित्रोत्पल्ला गंगा नाम हे।
जुग-जुग ले इहाँ धार बोहावय
जेकर लहरा हर यशगान करे हे
इहाँ के प्राचीन देव-देवाला ह
कला-संस्कृति के बखान करे हे।
ए माटी हर हमर धरोहर आए
पुरखा हमर ऋषि संत-बानी हे
गुरु-चेला जिहाँ महाप्रसाद के
मोक्ष-दुवार के अमर-कहानी हे।

मनरेगा में भ्रष्टाचार,निर्धन तबके के लोगों को रोजगार देने के नाम पर हो रही लूट

स्वराज श्रीवास्तव

ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंतरिक ऑडिट में मनरेगा में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। चालू वित्त वर्ष में 55 जिलों में 11 लाख से अधिक वित्तीय गड़बड़ियाँ पकड़ी गईं, जिनमें 300 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी शामिल है। यह दर्शाता है कि गरीबों को रोजगार देने के नाम पर बड़े पैमाने पर लूट हो रही थी, जिसमें ठेकेदार, अधिकारी और बैंक मैनेजर तक शामिल थे। केंद्र सरकार के नए स्वरूप में पारदर्शिता पर जोर है, लेकिन राज्यों को भी गंभीरता दिखानी होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंतरिक आडिट के चलते मनरेगा में भ्रष्टाचार के जैसे मामले सामने आए, वे चौंकाने वाले हैं। चालू वित्त वर्ष में देश के केवल 55 जिलों में कराए गए ऑडिट में वित्तीय गड़बड़ी के 11 लाख से ज्यादा मामले पकड़े गए, जिनमें 300 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी हुई। कोई भी अनुमान लगा सकता है कि जब केवल 55 जिलों में आठ माह में मनरेगा के तहत कराए गए कामों में इतनी गड़बड़ी देखने को मिली तो देश भर के सात सौ से अधिक जिलों में क्या स्थिति होगी?साफ है कि निर्धन तबके के लोगों को रोजगार देने के नाम पर लूट हो रही थी और कोई उसे रोकने वाला नहीं था। जिस तरह यह सामने आया कि जन कल्याण के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार में ठेकेदार,अधिकारी से लेकर बैंक मैनेजर तक शामिल थे, उससे यही स्पष्ट होता है कि सरकारी धन के बंदरबाट का एक तंत्र विकसित हो गया था। हालांकि रह-रहकर ऐसे सवाल उठते थे कि आखिर मरनेगा के तहत बुनियादी विकास के कितने ठोस काम हो रहे हैं, लेकिन उन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया? इसी तरह इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया गया कि रोजगार के नाम पर कब तक गड्ढे खोदे और भरे जाते रहेंगे? ऐसे सवालों के जवाब मांगने वालों को प्रायः यह सुनने को मिलता था कि उन्हें गरीबों के उत्थान की योजना रास नहीं आ रही है। कई बार तो मनरेगा में किसी तरह के बदलाव के सुझाव को इसलिए अनदेखा कर दिया जाता था कि इस योजना में महात्मा गांधी का नाम जुड़ा था। अभी हाल में जब मोदी सरकार ने इस योजना के नाम के साथ उसके रूप-स्वरूप में भी बदलाव किया तो विरोध में यह भी कहा गया कि इस सरकार को गांधी जी के नाम से बैर है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों ने सबसे अधिक विरोध किया,लेकिन उनके पास भ्रष्टाचार संबंधी सवालों का कोई जवाब नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य सरकारें मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार की इसलिए अनदेखी कर रही थीं कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार का अंशदान 90 प्रतिशत था? सच जो भी हो, इसकी अनदेखी न की जाए कि आम तौर पर राज्य सरकारें उन योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीरता नहीं दिखातीं,जिनका पैसा केंद्र से मिलता है। ऐसी योजनाएं भ्रष्टाचार का भी शिकार अधिक होती हैं।

अपने देश में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कागजों पर काम दिखाकर उसका पैसा हड़प लेना एक पुरानी बीमारी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बीमारी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। यह ठीक है कि मनरेगा के नए स्वरूप वीबी-जीरामजी के तहत केंद्र सरकार ने भुगतान में पारदर्शिता के साथ ठोस बुनियादी कामों पर जोर दिया है,लेकिन उसके साथ राज्यों को भी सुनिश्चित करना होगा कि वास्तव में ऐसा ही हो।

पाकिस्तान के रास्ते जाता बांग्लादेश

इस्लामिक कट्टरपंथ और भारत के प्रति घृणा हावी

दिव्य कुमार सोती

बांग्लादेश के हालात बिगड़ने के साथ यह भी दिख रहा है कि वहां की अंतरिम सरकार भारत से संबंध सुधारने के बजाय बिगाड़ने पर अमादा है। उसे न तो अपने यहां के हिंदुओं की हत्याओं की कोई परवाह है और न ही भारत विरोधी तत्वों के बेलगाम होते जाने की। वह इन तत्वों पर लगाम लगाने के बजाय उन्हें शह ही अधिक दे रही है। बांग्लादेश के हालात बिगड़ने के साथ यह भी दिख रहा है कि वहां की अंतरिम सरकार भारत से संबंध सुधारने के बजाय बिगाड़ने पर अमादा है। उसे न तो अपने यहां के हिंदुओं की हत्याओं की कोई परवाह है और न ही भारत विरोधी तत्वों के बेलगाम होते जाने की। वह इन तत्वों पर लगाम लगाने के बजाय उन्हें शह ही अधिक दे रही है। अपने यहां भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए बांग्लादेश एक ओर जहां अपनी क्रिकेट टीम को भारत में आयोजित होने वाले टी-20 विश्व कप में भेजने में आनाकानी कर रहा है, वहीं पाकिस्तान से अपने संबंध प्रगाढ़ कर रहा है।बांग्लादेश में जो हालात हैं,वे हमारी भूलों की भी देन हैं। ऐसी ही भूल हमने कश्मीर को हड़पने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान के मामले में भी की थी। कश्मीर को महज एक राजनीतिक समस्या मानकर हम वहां राजनीतिक समाधान तलाशते रहे। इसके परिणाम क्या रहे, उससे सभी परिचित हैं। हमने कोई सबक नहीं सीखा और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लाभाषी मुसलमानों और हिंदू अल्पसंख्यकों का पाकिस्तानी फौज द्वारा किए जा रहे नरसंहार को रोकने और बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए भारत ने पाकिस्तानी सेना से युद्ध लड़ा।

जिस समय भारत बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में कूदा,उस समय तक

पाकिस्तान की फौज 25 लाख बांग्लाभाषी मुसलमानों और हिंदुओं का नरसंहार कर चुकी थी और लाखों महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो चुका था। पाकिस्तान की फौज बंगाली मुसलमानों की नस्ल बदलने के लिए रेप कैंप संचालित कर रही थी। इन कैंपों में जन्मे हजारों बच्चों के पुनर्वास के लिए बाद में बांग्लादेश की सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दत्तक ग्रहण कार्यक्रम चलाना पड़ा।

लगभग 4000 भारतीय सैनिकों के बलिदान के बाद ये पाशविक अत्याचार बंद हुए और बांग्लादेश का निर्माण हुआ,परंतु हमने न तो इन अत्याचारों के अपराधी एक भी पाकिस्तानी सैनिक या सैन्य अधिकारियों को सजा दी और न ही इन जनसंहारों और अत्याचारों में पाकिस्तानी फौज का साथ देने वाले स्थानीय जमाती रजाकारों को ही मिटा डालने के लिए कुछ किया। भारत ने सोचा कि बांग्लादेश के मुसलमान पाकिस्तानी फौज और जमातियों के इन भयावह अत्याचारों को झेलने के बाद अब कभी भी इस्लामिक कट्टरपंथ के रास्ते नहीं चलेंगे और न ही पाकिस्तान से हाथ मिलाने की कभी सोचेंगे।

इसी गलत आकलन के आधार पर बंगाली मुसलमानों के लिए तो भारत ने पूरा नया देश बनाकर दे दिया, परंतु वहां रह रहे हिंदुओं और बौद्धों को एक बार फिर से वहां के मुस्लिम समाज के भरोसे छोड़ दिया।

भारत में नीति-निर्माता भूल गए कि 1946 में बंगाली मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का साथ देते हुए जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई थी और नोआखाली में हिंदुओं के नरसंहार को अंजाम दिया था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले अधिकतर नेता और सैन्य अधिकारी मुस्लिम लीग और पाकिस्तानी फौज में रह चुके थे।

भारत ने पाकिस्तान से अलग होकर बने नए देश बांग्लादेश के नेताओं और सेना पर इतना भरोसा किया कि चटगांव हिल ट्रैक्ट्स जैसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी बांग्लादेश के कब्जे में ही छोड़ दिया, जबकि 1947 के बंटवारे में चटगांव हिल ट्रैक्ट्स भारत के हिस्से में आने चाहिए थे, क्योंकि भारत-पाकिस्तान बंटवारे के अंतर्गत बंगाल का बंटवारा हुआ था और चटगांव हिल ट्रैक्ट्स उस समय बंगाल का भाग नहीं था। न ही वह मुस्लिम बहुल था,जो पाकिस्तान को दिया जाता।

यही कारण था कि वहां की जनता को लगा था कि उनका भारत का भाग बनना निश्चित है और 15 अगस्त, 1947 को वहां तिरंगा लहराया भी गया था,परंतु बंगाल बाउंड्री कमीशन ने अप्रत्याशित रूप में 17 अगस्त,1947 को चटगांव हिल ट्रैक्ट्स को पाकिस्तान को दे दिया और पाकिस्तान की फौज ने वहां से तिरंगा उतारा।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

CMYK

युवती ने अपने साथियों के साथ सिने में चाकू गोदकर की युवक की हत्या

पुलिस ने आरोपी युवती को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 10 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

शहर के गांधीनगर वार्ड क्रमांक 7 में शुक्रवार रात एक दिल दहला देने वाली हत्या की घटना ने पूरे इलाके को चौंका दिया। देर रात एक अधेड़ व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई,और उसका शव सुबह के समय घटनास्थल पर पड़ा मिला। इस घटना की जानकारी गांधीनगर के पार्षद विपिन पांडेय ने पुलिस को दी,जिसके बाद गांधीनगर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

मृतक की पहचान 50 वर्षीय बबलू मंडल के रूप में हुई,जो सुभाषनगर के वार्ड क्रमांक 2 स्थित बाबरा पेट्रोल पंप के पास रहता था। बबलू मंडल अपने परिवार का पालन-पोषण ठेले पर काम करके करता था। उसके बेटे दीप मंडल ने पुलिस को बताया कि रात 10.30 बजे तक उसके पिता घर के पास बैठे थे,लेकिन सुबह उसे यह सूचना मिली कि उसके पिता का शव गांधीनगर के वार्ड क्रमांक 7 स्थित अंकिता एग सेंटर के पास पड़ा हुआ था। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद दीप और अन्य परिजनों ने शव की पहचान की। पुलिस ने जब घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की,तो उसमें एक युवती और दो युवक हत्या की घटना को अंजाम देते हुए नजर आए। फुटेज में युवती मृतक बबलू मंडल से विवाद करते हुए यह कहती हुई दिखी, 'तू मेरे को हाथ कैसे लगाया,तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं?' इसके बाद उसने अपने साथियों को बुलाया और उन्होंने बबलू मंडल को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। तीनों आरोपी बाद में घटनास्थल से फरार हो गए और निशिकांत भगत वाली गली की ओर भागे। पुलिस ने यह फुटेज सामने आने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए युवती सोनिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार,सोनिया 20 वर्ष की नशे की आदी युवती है,जो शराब,गांजा और इंजेक्शन जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करती थी। घटना के बाद मृतक की पत्नी सुधा मंडल ने बताया कि शुक्रवार शाम को युवती और एक युवक उनके पति के साथ मारपीट कर रहे थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। सुधा ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और उन्हें फांसी देने की अपील की है। गांधीनगर इलाके में नशे के कारोबार का बढ़ता प्रभाव इस घटना के बाद एक गंभीर मुद्दा बन गया है। पार्षद विपिन पांडेय ने भी इस पर चिंता जताते हुए कहा कि गांधीनगर अब नशे का गढ़ बनता जा रहा है। यहां शराब, गांजा,इंजेक्शन जैसे नशीले पदार्थों का कारोबार दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। यदि इस पर जल्द काबू नहीं पाया गया,तो आने वाले समय में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस समस्या पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है, ताकि इलाके में शांति और सुरक्षा बहाल हो सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांधीनगर में नशे का कारोबार युवाओं के लिए एक बड़ा आकर्षण बन चुका है। यहां के युवा शराब और गांजे के अलावा नशे के इंजेक्शनों के सेवन में भी शामिल हैं। यह पूरे इलाके के लिए चिंता का विषय बन चुका है। पुलिस ने नशे के कारोबार पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाने की बात की है,लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या इस पर कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस हत्या की घटना ने न केवल एक परिवार को प्रभावित किया है,बल्कि पूरे इलाके को इस बात की याद दिलाई है कि नशे का प्रभाव कितनी भयंकर स्थिति पैदा कर सकता है। पुलिस अब मामले की गहनता से जांच कर रही है और दो अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस घटना के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या नशे की बढ़ती लत को रोकने के लिए किसी ठोस उपाय की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

श्याम लाडला परिवार द्वारा आयोजित भजन संध्या 17 जनवरी को गांधी स्टेडियम में...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 10 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल का भव्य भजन संध्या का आयोजन 17 जनवरी को अंबिकापुर स्थित गांधी स्टेडियम में होने जा रहा है। उक्त कार्यक्रम श्याम लाडला परिवार अंबिकापुर द्वारा आयोजित किया गया है। कार्यक्रम से पूर्व श्याम लाडला परिवार के पदाधिकारियों व सदस्यों ने शहर के एक होटल में शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर कार्यक्रम की जानकारी दी। श्याम लाडला परिवार के अध्यक्ष राहुल गर्ग ने बताया कि मां महामाया की नगरी अंबिकापुर स्थित गांधी स्टेडियम में 17 जनवरी को प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल का भजन संध्या का आयोजन किया गया है। भजन कार्यक्रम शाम 6 बजे शुरू होगी जो देर रात तक चलेगी। भक्तों के लिए स्टेडियम का दोनों गेट कोर्ट के सामने व दुर्गा मंदिर के बगल के गेट को खुला रखा जाएगा। भजन संध्या कार्यक्रम में श्याम लाडला परिवार द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। इसके साथ भजन प्रेमियों की बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। इस भजन संध्या में कन्हैया मित्तल के साथ लव अग्रवाल, सुरेश राजस्थानी एवं पप्पू महाराज भी कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। श्याम लाडला परिवार के पदाधिकारियों ने बताया कि भजन संध्या कार्यक्रम में 7-8 हजार भजन प्रेमियों के शामिल होने की संभावना है। भक्तों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वहीं पार्किंग की व्यवस्था पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड, स्वामी विवेकानंद स्कूल परिसर,शिशु मंदिर स्कूल परिसर में की गई है। प्रेस वार्ता के दौरान उपाध्यक्ष रवि अग्रवाल,कोषाध्यक्ष मुकेश गोयल, सचिव कैलाश अग्रवाल,सदस्य अंकुर अग्रवाल, अंकित सिंघल,अभिषेक अग्रवाल,सतीश अग्रवाल, राजू अग्रवाल, गौरव केडिया, मनीष अग्रवाल व राहुल अग्रवाल शामिल रहे।

मनरेगा नाम परिवर्तन व बदलाव को लेकर कांग्रेस का विरोध, गरीबों के अधिकार पर हमला बताया

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 10 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

केन्द्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के नाम परिवर्तन और उसके मूल प्रावधानों में बदलाव को लेकर कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है। शनिवार को अंबिकापुर स्थित राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता एवं पूर्व केबिनेट मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह ने इन बदलावों को गरीबों के अधिकारों को समाप्त करने वाला कदम बताया। डॉ. प्रेमसाय सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वरोजगार के स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में मनरेगा कानून पारित किया था, जिसके तहत ग्रामीण मजदूरों को रोजगार की संवैधानिक गारंटी दी गई। योजना के लागू होने के बाद से अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्यदिवस सृजित हुए हैं और ग्रामीण भारत में 10 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया है, जिनमें तालाब, सहायक संरचनाएं और अन्य आधारभूत ढांचे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008-09 की वैश्विक आर्थिक मंदी हो या कोविड-19 का संकट,मनरेगा ने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैग की ऑडिट रिपोर्ट और देश-विदेश में किए गए लगभग 200 अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि यह योजना अत्यंत प्रभावी रही है। इसकी सफलता का मुख्य कारण रोजगार की संवैधानिक गारंटी थी, जिसके तहत मजदूर काम की मांग कर सकते थे और 15 दिन के भीतर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान था। इस योजना का शत-प्रतिशत बजट केन्द्र सरकार वहन करती थी, जिससे राज्य सरकारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ता था।

मूल प्रावधानों को किया गया है कमजोर : डॉ. सिंह ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने न केवल योजना के मूल प्रावधानों को कमजोर किया है,बल्कि महात्मा गांधी के नाम को हटाकर इसका नाम बदलकर 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण' कर दिया है। नई योजना में काम की संवैधानिक गारंटी समाप्त कर दी गई है। ग्राम पंचायतों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं और काम के आवंटन का अधिकार केन्द्र सरकार अपने पास रख रही है।

न्यूनतम मजदूरी की गारंटी समाप्त

उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों के तहत न्यूनतम मजदूरी की गारंटी भी समाप्त हो जाएगी और मजदूरी दर तय करने का अधिकार सरकार के पास होगा। साथ ही,बजट आवंटन को 60-40 के अनुपात में केन्द्र और राज्य सरकारों पर डाल दिया गया है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर राज्य इस योजना के क्रियान्वयन में रुचि नहीं लेंगे। इससे ग्रामीण रोजगार पूरी तरह समाप्त होने की आशंका है और 100 से 125 दिन रोजगार बढ़ाने का दावा भी जुमला साबित होगा। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि नई योजना में फसल अवधि के दौरान रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे बड़ी संख्या में भूमिहीन मजदूर प्रभावित होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा को कमजोर करना कारपोरेट हितों को साधने की नीति का हिस्सा है। अंत में कांग्रेस ने मांग की कि सरकार मनरेगा को मूल स्वरूप में बहाल करे, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन निर्धारित करे और रोजगार, मजदूरी व जवाबदेही की संवैधानिक गारंटी सुनिश्चित करे। प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक सहित अन्य कांग्रेस नेता शामिल रहे।

पति की मौत होते ही एग्रिमेंट जमीन को दूसरे से बेचा

महिला सहित दो पर रिपोर्ट दर्ज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 10 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

जमीन बिक्री के नाम पर 4 लाख रुपए धोखधड़ी किए जाने के मामले में कोतवाली पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। जानकारी के अनुससार संगीता दुबे पति स्व. संतोष धर दुबे कोतवाली क्षेत्र के स्कूल रोड की रहने वाली है। उसने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने पुलिस को बताया है कि मरे पति का निधन 15 अक्टूबर 2025 को हो गया है। निधन से पूर्व उन्होंने मायापुर स्थित खसरा नम्बर 1691/19 रकबा 0.028 हे. में से 0.014 लगभग 3.5 डिसमील जमीन खरीदने के लिए दीपक गुप्ता,दीपा गुप्ता और सोनमति गुप्ता से 6 मार्च 2024 को सौदा तय कर एडवांस के रूप में 1 लाख 25 हजार रुपए रजिस्टार कार्यालय में एग्रमेंट कर दिया था। दीपक गुप्ता ने कहा था कि अभी जमीन की कागजात की कमी है कुछ दिनों के बाद रजीस्ट्री कर देंगे। इस बीच दोनों के बीच दोस्ती हो गई। विश्वास में लेकर दीपक ने अन्य जगह जमीन खरीदने के लिए संतोष धर दुबे से एग्रिमेंट कर रुपए लिए थे। एग्रिमेंट की कॉपी दीपक ने स्वयं अपने पास रखा था। संतोष की मौत के बाद उसकी पत्नी प्रार्थिया संगीता दुबे द्वारा पूछे जाने पर दीपक कोई एग्रिमेंट न होने की बात कहने लगा। संगीता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि पति की मृत्यु के बाद दीपक,दीपा गुप्ता द्वारा एग्रिमेंट किए गए जमीन को बगैर जानकारी के दूसरे से बेच दिया। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी दीपक गुप्ता, दीपा गुप्ता के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

जीईसी अम्बिकापुर ने जीता एकीकृत क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 10 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ राज्य के तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एकीकृत क्रिकेट प्रतियोगिता में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज (जीईसी) अम्बिकापुर की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में यूटीडी सीएसवीटीयू को हराकर विजेता का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मैच में खिलाड़ियों ने बेहतरीन टीम भावना,अनुशासन और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। पूरे टूर्नामेंट के दौरान जीईसी अम्बिकापुर की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए सभी को प्रभावित किया। इस उपलब्धि पर प्राचार्य डॉ. राम नारायण खरे एवं स्पोर्ट्स ऑफिसर मनोज कुमार देवांगन ने टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। इन्होंने कहा कि सीईसी अम्बिकापुर की टीम ने उत्कृष्ट खेल भावना और मेहनत के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है। यह पूरे कॉलेज के लिए गौरव का क्षण है।

संयुक्त संचालक ने विभिन्न शासकीय अस्पतालों का किया निरीक्षण,25 कर्मचारी पाए गए अनुपस्थित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 10 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. अनिल शुक्ला ने शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बतौली,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरगीडीह और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रघुनाथपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बतौली में लैब में अव्यवस्थित स्यूटम स्लाईड पाए गए और टीबी मरीजों की काउंसलिंग की उपलब्धि कम रही। इसके अतिरिक्त,केंद्र में साफ-सफाई का अभाव था और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आईईसी प्रदर्शन की कमी पाई गई। निरीक्षण के दौरान 25 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरगीडीह में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए और भवन सुधार के लिए भी कदम उठाने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही, 102 की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। यहां भी तीन कर्मचारी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए।

जेडी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रघुनाथपुर में सुरक्षा व्यवस्था और साफ-सफाई के सुधार के निर्देश दिए गए।

महिला और पुरुष वार्ड में मरीजों की अलग-अलग भर्ती सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। यहां भी तीन कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की बात कही है।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व...भारत की अटूट आस्था और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 10 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

सोमनाथ मंदिर पर वर्ष 1026 में हुए पहले अभिलिखित आक्रमण के 1000 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को भारत की अटूट आस्था, सांस्कृतिक स्वाभिमान और सनातन चेतना के प्रतीक के रूप में मनाया जा रहा है। यह पर्व केवल एक ऐतिहासिक स्मरण नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा,आस्था और पुनर्जागरण का उत्सव है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सरगुजा के कार्यकर्ताओं द्वारा जिले के विभिन्न मंदिरों में पहुँचकर भगवान शिव का जलाभिषेक, पूजन एवं आरती कर राष्ट्र,समाज और धर्म की अखंडता के लिए प्रार्थना की गई। अम्बिकापुर महामाया मंडल एवं समलाया मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जोड़ा पीपल एवं सत्तीपारा स्थित मंदिरों में भगवान शिव की विधिवत पूजा-अर्चना की। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, अस्मिता और अदम्य साहस का प्रतीक है। बार-बार आक्रमणों के बावजूद सोमनाथ का पुनर्निर्माण यह संदेश देता है कि भारत की आस्था को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता।

अवैध धान संग्रहण पर प्रशासन की कार्रवाई, 460.80 क्विंटल धान जप्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 10 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

जिले में अवैध धान संग्रहण एवं कारोबार पर रोक लगाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान आज विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध धान के प्रकरण दर्ज कर धान जप्ती की कार्यवाही की गई। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए संग्रहित धान पाए जाने पर संबंधित व्यापारियों के विरुद्ध प्रकरण बनाया गया। जांच में हनुमंत ट्रेडर्स,असोला से 288 क्विंटल, केसरवानी ट्रेडर्स, परसा से 116 क्विंटल तथा विकास ट्रेडर्स, सोनपुरकला से 56.8 क्विंटल धान जप्त किया गया। इस प्रकार कुल 460.80 क्विंटल अवैध धान जप्त किया गया है। खाद्य विभाग एवं मंडी टीम द्वारा मौके पर दस्तावेजों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की गई तथा जप्त धान को सुरक्षित अभिरक्षा में लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई शासन के निर्देशानुसार धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने तथा अवैध भंडारण एवं व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए की गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध धान संग्रहण, परिवहन अथवा व्यापार में संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

दोपहिया वाहन चालको द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही

ड्रंक एंड ड्राइव के 02 मामले मे वाहन चालको कों 20000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 10 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

सडक दुर्घटनाओ कों कम करने की दिशा मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सखूती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे थाना मणीपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान बुलेट मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/सीजेड/1954 के चालक आकाश सोनी आत्मज राजू सोनी उम्र 25 वर्ष महामाया चौक के पास थाना अंबिकापुर एवं अपाचे मोटरसायकल चालक क्रमांक सीजी/14/एमटी/0699 के चालक बन्नू दास आत्मज नैनदास उम्र 32 वर्ष साकिन बरढोढ़ी कों ब्रेथ ऐनालाइजर से मौक़े पर चेक किये जाने पर शराब के नशे मे धुत्त होकर वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालको के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अलग अलग प्रकरण दर्ज कर दोनों मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त दोनों प्रकरणों मे वाहन चालक कों 10000/- रुपये, 10000/- के अलग अलग अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।

मुन्ना लाल चौधरी बनाए गए किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष

-संवाददाता-
राजपुर, 10 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के राजपुर निवासी मुन्ना लाल चौधरी को उनके बलरामपुर जिला अध्यक्ष रहने के दौरान पार्टी ने उनके उपलब्धियों को देखते हुए भाजपा किसान मोर्चा का प्रदेश प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर पार्टी से जुड़े लोगों में हर्ष व्याप्त है।

बलरामपुर जिले के राजपुर निवासी मुन्ना लाल चौधरी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनने से भाजपा किसान मोर्चा को एक मजबूत और अनुभवी नेतृत्व मिला है। बलरामपुर जिले के किसानों के मसीहा कहे जाने वाले, सरल, सहज, मिलनसार और मृदभाषी व्यक्तित्व के धनी वरिष्ठ भाजपा नेता मुन्ना लाल चौधरी को भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ संगठन ने एक बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि मुन्ना लाल चौधरी इससे पहले भाजपा के जिला उपाध्यक्ष और भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष जैसे अहम पदों पर रहते हुए किसानों की आवाज़ को समय समय पर मजबूती से उठाते रहे हैं। उनके नेतृत्व में बलरामपुर जिले में किसान मोर्चा को एक अलग पहचान मिली।

CMYK

अदृश्य कैमरों से जबरन चालान? ई-चालान व्यवस्था पर जनता में आक्रोश

एसएमएस आया...चालान कटा-गलत चालान पर न्याय कहां?

- डिजिटल चालान या वसूली का खेल? वाहन मालिकों की बढ़ी परेशानी
- दस्तावेज पूरे, फिर भी चालान! ई-चालान प्रणाली कटघरे में...
- ई-चालान व्यवस्था से परेशान वाहन मालिक,शिकायत तंत्र पर सवाल
- ऑनलाइन चालान प्रणाली में खामियां, जनता में बढ़ता असंतोष
- अदृश्य कैमरों से निगरानी,लेकिन अपील व्यवस्था गायब
- कैमरे दिखे नहीं,चालान कट गया ई-चालान से वाहन मालिक परेशान
- डिजिटल निगरानी तेज गलत चालान पर जवाबदेही नहीं...
- ऑनलाइन ट्रैफिक चालान को लेकर लोगों की शिकायतें...

न्यूज डेस्क

रायपुर/सरगुजा,10 जनवरी 2026 (घटती-घटना)। प्रदेश में यातायात व्यवस्था को आधुनिक और डिजिटल बनाने के नाम पर लगाए गए अदृश्य ट्रैफिक कैमरे अब आम जनता के लिए राहत नहीं,बल्कि परेशानी और आक्रोश का कारण बनते जा रहे हैं,सड़कों पर बिना जानकारी लगाए गए इन कैमरों के जरिए ऑनलाइन ई-चालान काटे जा रहे हैं और वाहन मालिकों के मोबाइल पर सीधे एसएमएस भेज दिया जा रहा है,लेकिन सवाल यह है कि क्या हर चालान सही है? और यदि चालान गलत है तो न्याय कहां मिलेगा? डिजिटल तकनीक का उद्देश्य जनता को सुविधा देना है,न कि उसे डर और भ्रम में डालना,यदि ई-चालान व्यवस्था पारदर्शी,जवाबदेह और न्यायसंगत नहीं बनी, तो यह जनविश्वास को तोड़ने का काम करेगी, अब बड़ा सवाल यही है ऑनलाइन ई-चालान जनता की सुविधा है,या अदृश्य कैमरों के जरिए जबरन वसूली का नया हथियार?

चालान कट गया एसएमएस आया और अब करें तो करें क्या?

वाहन मालिकों का कहना है कि अचानक मोबाइल पर चालान कटने का मैसेज आ जाता है, मैसेज में केवल चालान नंबर और भुगतान का निर्देश होता है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि चालान क्यों कटा,सबूत क्या है,और यदि चालान गलत है तो उसकी शिकायत या अपील कहां करें,अधिकांश लोगों को यह भी नहीं पता कि गलत चालान होने पर वे किस विभाग, किस अधिकारी या किस कार्यालय से संपर्क करें। ऐसे में आम नागरिक खुद को लाचार और ठगा हुआ महसूस कर रहा है।

जनता में बढ़ता आक्रोश

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया,चाय दुकानों,और आम बातचीत में ई-चालान को लेकर गुस्सा और असंतोष साफ दिखाई दे रहा है, लोगों का कहना है कि वे नियमों के पालन के खिलाफ नहीं हैं,चालान से भी परहेज नहीं, लेकिन गलत चालान और अपील की व्यवस्था न होना उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान कर रहा है।

दस्तावेज पूरे, फिर भी चालान-तकनीकी गलती की सजा जनता को...

कई वाहन मालिकों का दावा है कि उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस,आरसी, बीमा,और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट पूरी तरह मौजूद हैं,इसके बावजूद 'दस्तावेज नहीं होने' के नाम पर ई-चालान काट दिया गया,लोगों का कहना है कि यदि सर्वर डाउन है,डाटा अपडेट नहीं है,या किसी तकनीकी कारण से दस्तावेज सिस्टम में नहीं दिख रहे, तो इसकी जिम्मेदारी वाहन मालिक की कैसे हो सकती है? लेकिन हकीकत यह है कि तकनीकी खामी का खामियाजा सीधे जनता को भुगतना पड़ रहा है।

डिजिटल सुविधा या जबरन वसूली?

अब लोग खुलकर सवाल पूछने लगे हैं क्या यह सच में ऑनलाइन सुविधा है, या फिर सरकारी खजाना भरने का नया तरीका? आरोप लग रहे हैं कि अदृश्य कैमरों की मॉनिटरिंग करने वाले कर्मचारी बिना मानवीय सत्यापन के,बेवजह चालान काट रहे हैं,मानो उन्हें अधिक से अधिक चालान काटने का लक्ष्य दिया गया हो,जनता पूछ रही है क्या सरकार ने आर्थिक तंगी से उबरने के लिए जबरदस्ती चालान वसूली का रास्ता चुना है?

शिकायत व्यवस्था पूरी तरह नदारद

सबसे गंभीर और चिंताजनक पहलू यह है कि ई-चालान के एसएमएस में कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं, कोई शिकायत पोर्टल का लिंक नहीं,और न ही यह जानकारी कि गलत चालान पर कहां और कैसे अपील की जाए,ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह व्यवस्था और भी मुश्किल है,जहां डिजिटल जानकारी सीमित है। लोग मजबूरी में चालान भर रहे हैं,भले ही उन्हें पूरा यकीन हो कि चालान गलत है।

परिवहन विभाग से सीधे सवाल

अब जनता सीधे परिवहन विभाग और शासन से जवाब चाहती है क्या हर ई-चालान से पहले मानवीय जांच होती है? तकनीकी गड़बड़ी की जिम्मेदारी कौन लेगा? गलत चालान होने पर सरल, सुलभ और त्वरित अपील व्यवस्था क्यों नहीं? क्या अदृश्य कैमरे केवल निगरानी के लिए हैं या वसूली के लिए?

जनता की मांग—सुधार जरूरी वाहन मालिकों की मांग है कि–

- गलत ई-चालान के लिए स्पष्ट शिकायत और अपील प्रणाली बनाई जाए।
- हर चालान एसएमएस में हेल्पलाइन नंबर, वेबसाइट और संपर्क अधिकारी की जानकारी हो।
- तकनीकी कारणों से कटे चालानों को तुरंत निरस्त किया जाए।
- डिजिटल व्यवस्था के साथ मानवीय विवेक और जवाबदेही भी तय की जाए।

दैनिक घटती घटना अखबार का सुझाव, ई-चालान व्यवस्था में सुधार जरूरी

डिजिटल व्यवस्था को लागू करना समय की आवश्यकता है, लेकिन डिजिटल सुविधा यदि जनता के लिए परेशानी बन जाए, तो उस पर सुधार भी उतना ही जरूरी है,ई-चालान और अदृश्य कैमरों की व्यवस्था को लेकर सामने आ रही शिकायतें बताती हैं कि प्रणाली में तकनीकी के साथ-साथ मानवीय संवेदनशीलता का अभाव है, दैनिक घटती घटना अखबार का स्पष्ट सुझाव है कि हर ई-चालान के साथ हेल्पलाइन नंबर अनिवार्य किया जाए,चालान के एसएमएस में एक ऐसा सक्रिय हेल्पलाइन नंबर हो, जहां वाहन मालिक अपनी समस्या दर्ज करा सके और सही मार्गदर्शन पा सके,ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा दी जाए,यदि वाहन मालिक के पास वैध दस्तावेज हैं और तकनीकी कारणों से चालान कट गया है,तो उसे एक निर्धारित पोर्टल या लिंक के माध्यम से आरसी,बीमा,ड्राइविंग लाइसेंस,प्रदूषण प्रमाण पत्र अपलोड करने की सुविधा मिले,दस्तावेज सही पाए जाने पर चालान स्वतः या त्वरित जांच के बाद निरस्त किया जाए,ऐसे में दैनिक घटती-घटना अखबार का मानना है कि परिवहन विभाग को तुरंत कुछ व्यावहारिक और जनहितकारी सुधार करने चाहिए, ताकि आम वाहन मालिकों को अनावश्यक मानसिक और आर्थिक कष्ट से राहत मिल सके।

हर जिले में ऑफलाइन सहायता केंद्र अनिवार्य हों...

आज भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन प्रक्रिया से दूर हैं, स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं रखते,या डिजिटल प्रक्रिया समझने में असमर्थ हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रत्येक जिले में एक समर्पित ई-चालान सहायता केंद्र होना चाहिए,जहां वे अपने दस्तावेज दिखाकर गलत चालान के निरस्तीकरण के लिए आवेदन कर सकें।

तकनीकी गलती की सजा जनता को न मिले

यदि सर्वर डाउन है, डेटा अपडेट नहीं है या सिस्टम में तकनीकी खामी है,तो उसकी जिम्मेदारी वाहन मालिक पर नहीं डाली जानी चाहिए,ऐसी स्थिति में चालान को अस्थायी रूप से रोका जाए जब तक सत्यापन न हो जाए,पारदर्शिता और भरोसा सबसे जरूरी,डिजिटल चालान व्यवस्था तभी सफल होगी जब उसमें पारदर्शिता,जवाबदेही और त्वरित समाधान शामिल होगा।

दस्तावेज समाप्ति पर 10 दिन की मोहलत-

अखबार का स्पष्ट सुझाव है कि किसी भी दस्तावेज (बीमा, फिटनेस, पॉल्यूशन आदि) की तिथि समाप्त होने के बाद कम से कम 10 दिन की मोहलत दी जाए,कई बार वाहन मालिक दस्तावेज नवीनीकरण की प्रक्रिया में होता है,बीमा या फिटनेस हो चुका होता है,लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट नहीं हो पाता,या कार्यालय अवकाश/तकनीकी कारणों से दस्तावेज पूर्ण नहीं हो पाते,ऐसी स्थिति में सीधे चालान काटना अन्यायपूर्ण है।

हाल ही में समाप्त दस्तावेजों पर रियायत

यदि सिस्टम में यह स्पष्ट दिख रहा है कि कोई दस्तावेज हाल ही में (10 दिन के भीतर) समाप्त हुआ है, तो उस वाहन मालिक को चालान से राहत दी जानी चाहिए,और नवीनीकरण के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए,इससे ईमानदार वाहन मालिकों को राहत मिलेगी और व्यवस्था पर भरोसा भी बढ़ेगा।

खबर का निष्कर्ष परेशानी नहीं समाधान जरुरी है...

ई-चालान व्यवस्था कानून पालन के लिए है, आम नागरिक को डराने या परेशान करने के लिए नहीं, यदि परिवहन विभाग उपरोक्त सुझावों पर अमल करता है,तो जनता का भरोसा बढ़ेगा, अनावश्यक विवाद कम होंगे,और डिजिटल व्यवस्था वास्तव में सुविधा का माध्यम बन सकेगी, दैनिक घटती घटना का मानना है कि तकनीक का उपयोग तब सफल होता है,जब वह आम आदमी के पक्ष में खड़ी दिखाई दे,न कि उसके खिलाफ,अब उम्मीद है कि परिवहन विभाग जनभावनाओं को समझते हुए आवश्यक सुधारों पर गंभीरता से विचार करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

ईरान में हिंसक प्रदर्शन, 217 लोगों की मौत

सेना बोली...बच्चों को प्रदर्शन से दूर रखें वरना गोली लगने पर शिकायत मत करना

तेहरान,10 जनवरी 2026। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 217 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। टाइम मैगजीन ने तेहरान के एक डॉक्टर के हवाले से बताया कि राजधानी के सिर्फ छह अस्पतालों में कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है, जिनमें ज्यादातर की मौत गोली लगने से हुई हैं। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन तेज होने पर कई जगहों पर गोलीबारी की थी, इसके बाद से लगातार कार्रवाई जारी है। इस बीच रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक अधिकारी ने सरकारी टीवी से बात करते चेतावनी दी कि माता-पिता अपने बच्चों को प्रदर्शनों से दूर रखें, अगर उन्हें गोली लगे तो शिकायत मत करना।

सरकार प्रदर्शन रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही

पहले कुछ दिनों तक यह साफ नहीं था कि सरकार क्या रुख अपनाएगी। खुद एंटी राइट्स पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बल भ्रम में हैं। किसी को ठीक से नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन सामने आई खूनी तस्वीरों और सख्त बयानों से साफ हो गया कि अब पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले सरकार ने देशभर में इंटरनेट और फोन सर्विस लगभग बंद कर दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो ईरानी सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

ईरान में महंगाई से आम लोगों में नाराजगी बढ़ी

देशभर में GenZ आक्रोश में है। इसका कारण आर्थिक बदहाली रहा है। दिसंबर 2025 में ईरानी मुद्रा रियाल गिरकर करीब 1.45 मिलियन प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। साल की शुरुआत से रियाल की कीमत लगभग आधी हो चुकी है। यहां महंगाई चरम पर पहुंच गई है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 72% और दवाओं की कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा सरकार द्वारा 2026 के बजट में 62% टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव ने आम लोगों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है।

खामेनेई की अपील-ट्रम्प को खुश करने के लिए देश बर्बाद न करें...

ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने शनिवार को देशभर में प्रदर्शनों के बीच शुक्रवार को पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया था। ईरान की सरकारी टीवी ने उनका भाषण प्रसारित किया। खामेनेई ने कहा कि ईरान 'विदेशियों के लिए काम करने वाले भाड़े के लोगों' को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनों के पीछे विदेशी एजेंट हैं जो देश में हिंसा भड़का रहे हैं। खामेनेई ने कहा कि देश में कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करना चाहते हैं। लेकिन ईरान की एकजुट जनता अपने सभी दुश्मनों को हराएगी। उन्होंने ट्रम्प से कहा कि ईरान के मामलों में दखल देने के बजाए वे अपने देश की समस्याओं पर ध्यान दें।

एक्सपर्ट्स को आशंका-सरकार बेरहम कार्रवाई से नहीं हिचकेगी

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब जब प्रदर्शन मध्यम वर्गीय इलाकों तक फैल गए हैं,तो सरकार बेरहमी से कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी। उनका मानना है कि आने वाले दिनों में हताहतों की संख्या और बढ़ सकती है। ईरान पहले से ही इजराइल के साथ संघर्ष,अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों, गिरती अर्थव्यवस्था,बिजली और पानी की किल्लत जैसी समस्याओं से जूझ रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1 करोड़ जानें बचाई : शहबाज शरीफ

ट्रंप ने अलापा भारत-पाक संघर्ष रोकने का दावा

वॉशिंगटन,10 जनवरी 2026। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़े संघर्ष को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। ट्रंप के अनुसार,पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका दौरे के दौरान सार्वजनिक रूप से उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा था कि ट्रंप की पहल से कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बची।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किया धन्यवाद

व्हाइट हाउस में शीर्ष तेल और गैस कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात के दौरान मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण थे और हालात युद्ध की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहां आए और उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान संकट में न्यूनतम दस मिलियन जानें बचाईं।' उन्होंने यह भी कहा कि भारत-पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव में हालात इतने बिगड़ चुके थे कि दोनों देशों के आठ लड़ाकू विमान हवा में मार गिराए गए, लेकिन उनके हस्तक्षेप से परमाणु युद्ध जैसी स्थिति बनने से पहले ही मामला शांत हो गया। हालांकि, भारत ने इन दावों को लगातार खारिज किया है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि भारत-पाकिस्तान के बीच शांति किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से नहीं बल्कि सीधे दोनों देशों के सैन्य संवाद के जरिए हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह डींग नहीं हांकना चाहते, लेकिन इतिहास में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने उनसे ज्यादा युद्ध रुकवाए हों। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने आठ बड़े युद्धों को समाप्त कराया, जिनमें कुछ संघर्ष 25 से 36 वर्षों से जारी थे। भारत के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले (अप्रैल 2025) में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से संपर्क कर संघर्षविराम का अनुरोध किया,जिस पर दोनों पक्षों की सहमति बनी। भारत ने साफ किया है कि शांति प्रक्रिया पूरी तरह द्विपक्षीय थी और इसमें किसी विदेशी नेता या देश की भूमिका नहीं रही।

कट्टरपंथ की भेंट चढ़ा पौष पर्व...बांग्लादेश में मकर संक्रांति को बताया 'हराम', जारी हुआ फतवा

बांग्लादेश,10 जनवरी 2026। बांग्लादेश में जारी उथल-पुथल के बीच अब हिंदू त्योहार भी इस्लामिक कट्टरपंथियों के सीधे निशाने पर आ गए हैं। बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग माने जाने वाले 'मकर संक्रांति' या 'पौष पर्व' को लेकर इस बार कट्टरपंथियों ने कड़ा रुख अपनाया है। यूनुस सरकार के नेतृत्व में फल-फूल रहे चरमपंथी गुटों ने इस उत्सव को मनाने के खिलाफ बाकायदा फतवा जारी कर दिया है। इस पावन त्योहार को 'इस्लामी मान्यताओं के विरुद्ध' और 'हराम' घोषित किया गया है।

हिंदू बहुल इलाकों में संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं कि किसी भी प्रकार का सार्वजनिक समारोह आयोजित न किया जाए। इस नए फरमान ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के मन में गहरे खौफ और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। मकर संक्रांति का अर्थ है खेतों से आए नए चावल का उत्सव और घरों में बनने वाले हजारों तरह के स्वादिष्ट 'पीठेपुली'। सदियों से यह परंपरा रही है कि मकर संक्रांति के अवसर पर बंगाल के हर घर में महिलाएं पारंपरिक पकवान बनाती हैं, जिनकी खुशबू पूरे परिवेश को आनंदित कर देती है।

ऐतिहासिक रूप से, दोनों बंगाल (पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश) मिलकर 'नबान्न' और 'पौष पर्व' को धूमधाम से मनाते आए हैं। पद्मा नदी के किनारों पर यह उत्सव साझी विरासत का प्रतीक था। लेकिन 'नए बांग्लादेश' में कट्टरपंथ की लहर ने इस खुशहाली को छीन लिया है। पूरे देश में यह दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है कि इस उत्सव में शामिल होना इस्लाम के विरुद्ध है, जिससे सामाजिक सौहार्द पूरी तरह बिगड़ गया है।

वेनेजुएला का तेल भारत को देगा अमेरिका...ट्रम्प दुनिया की बड़ी ऑयल कंपनियों के अफसरों से मिले,रिलायंस भी तेल खरीद सकती है...

वॉशिंगटन,10 जनवरी 2026। अमेरिका,भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने की इजाजत दे सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रम्प प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारी के मुताबिक यह सब अमेरिका की निगरानी और शर्तों के साथ होगा। हालांकि इससे जुड़ी शर्तें क्या हैं,इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से जो व्यापार रुका हुआ था,वह अब फिर से शुरू हो सकता है। वहीं,रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रिलायंस भी चाहती है कि अमेरिका उसे वेनेजुएला का तेल खरीदने की इजाजत दे दे। दूसरी ओर ट्रम्प ने शुक्रवार को व्हाइट में दुनिया की बड़ी तेल कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। यहां उन्होंने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में करीब 9 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात कही।

अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत ने तेल खरीदना बंद किया था : वेनेजुएला पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का सदस्य है। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन वह वैश्विक सप्लाई का सिर्फ करीब 1% ही देता है। अमेरिका ने 2019 में वेनेजुएला पर बहुत कड़े आर्थिक प्रतिबंध (सेंक्शंस) लगा दिए थे, अमेरिका ने सेकेंडरी सेंक्शंस भी लगा दिए, यानी जो भी देश या कंपनी वेनेजुएला से तेल खरीदती है,उसे अमेरिकी बाजार में व्यापार करने या बैंकिंग सुविधाओं से रोक दिया जा सकता था। इस वजह से कई देशों ने वेनेजुएला का तेल खरीदना बंद कर दिया। भारत भी वेनेजुएला से बहुत ज्यादा तेल खरीदता था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि तब भारत अपने कुल तेल आयात का लगभग 6% वेनेजुएला से लेता था। अगर भारत को फिर से वेनेजुएला का तेल खरीदने की अनुमति मिल जाती है, तो उसे अलग-अलग देशों से तेल मंगाने का एक और विकल्प मिलेगा। इससे भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने कुछ समय के लिए (2023-2024 में) वेनेजुएला पर आंशिक रूप से सेंक्शंस ढीले किए, जिससे भारत ने फिर से वेनेजुएला से तेल खरीदा। 2024 में भारत का आयात औसतन 63,000 से 1 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया।

मध्यान्ह भोजन पर सियासत हावी?

आत्मानंद विद्यालय पटना में पोषण योजना बनी खींचतान का केंद्र

पोषण या कमीशन? आत्मानंद स्कूल पटना में मध्यान्ह भोजन संचालन पर राजनीतिक दबाव के आरोप

बिना शिकायत बदला जा रहा मध्यान्ह भोजन समूह, आत्मानंद विद्यालय पटना में उठा बड़ा सवाल

बच्चों के भोजन पर राजनीति! आत्मानंद विद्यालय पटना में मध्यान्ह भोजन को लेकर जोर-आजमाइश

-रवि सिंह-

कोरिया/पटना, 10 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

मध्यान्ह भोजन योजना या राजनीतिक लाभ? आत्मानंद स्कूल पटना में विवाद गहराया

क्लीन चिट के बावजूद हटाने की तैयारी, आत्मानंद विद्यालय में मध्यान्ह भोजन पर सियासी दखल

पोषण योजना पर 'दबाव तंत्र': आत्मानंद विद्यालय पटना में मध्यान्ह भोजन को लेकर बवाल

शासकीय स्कूलों में बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई मध्यान्ह भोजन योजना अब राजनीतिक हस्तक्षेप और आर्थिक लाभ के आरोपों के घेरे में आ गई है। कोरिया जिले के नगर पंचायत पटना स्थित आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पटना में मध्यान्ह भोजन संचालन को लेकर इन दिनों जबरदस्त खींचतान चल रही है। सूत्रों के मुताबिक, यहां योजना का संचालन बेहतर ढंग से कर रहे समूह को हटाकर राजनीतिक दल से जुड़े एक कार्यकर्ता के समूह को जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी की जा रही है।

वैसे वर्तमान में जिस समूह के पास संचालन की जिम्मेदारी है उसकी शिकायत एक भी नहीं पाए जाने की बात सामने आई है,यहां तक कि स्कूल प्रबंधन,छात्र छात्रा भी इस बदलाव के समर्थन में नहीं हैं,वैसे सूत्रों की माने तो वर्तमान में संचालनकर्ता समूह की कई शिकायतें की गई और जिसकी वृहद जांच भी हुई लेकिन जांच में भी जब कोई कमी सामने नहीं आई तब नया हथकंडा अपनाया गया और अब स्थानीय बनाम बाहरी कहकर संचालन की जिम्मेदारी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को प्रदान करने की तैयारी पूरी हुई है,वैसे इस मामले में भारी लेनदेन भी खबरें सुनी जा रही हैं,बताया जा रहा है कि स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा जो संचालन के संबंध में सामने लाकर वर्तमान समूह को हटाने की तैयारी है वह स्थानीय लोगों द्वारा ही संचालित समूह है, वैसे यदि सूत्रों की माने तो महिला स्वयं सहायता समूहों की कहानी हर जगह ऐसी ही है,कई जिम्मेदारी प्राप्त करने अन्य लोगों के समूहों से लोग कोई जिम्मेदारी प्राप्त करते हैं और उसका संचालन करते हैं,जो इस मामले का भी सच है।वैसे पटना आत्मानंद मामले में यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई जो एक मध्यान्ह भोजन संचालन समूह को तब बदला जा रहा है जब उसकी कोई शिकायत नहीं,शिक्षक, पालक,छात्र जिससे संतुष्ट हैं और जो जांच में भी दोषी नहीं पाया गया वहीं वर्तमान में जब शिक्षा सत्र समाप्ति की ओर है।

सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर सवाल

मध्यान्ह भोजन योजना का मूल उद्देश्य स्कूली छात्र-छात्राओं को पौष्टिक भोजन देकर उनके स्वास्थ्य में सुधार और स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाना है। आमतौर पर इसका संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाता है,जिनकी निगरानी शिक्षक,शाला प्रबंधन समिति और पालक समिति करती है। नियमों के अनुसार,जब तक किसी संचालनकर्ता समूह के विरुद्ध गंभीर शिकायत या अनियमितता प्रमाणित न हो,तब तक उसे बदला नहीं जाता,लेकिन आत्मानंद विद्यालय पटना में हालात इसके उलट बताए जा रहे हैं।

बिना शिकायत समूह बदलने की कवायद

सूत्रों के अनुसार,वर्तमान में जिस समूह के पास मध्यान्ह भोजन संचालन की जिम्मेदारी है उसके खिलाफ एक भी प्रमाणित शिकायत नहीं, पूर्व में हुई जांच में भी कोई कमी नहीं पाई गई, शिक्षक, पालक और छात्र संचालन से संतुष्ट बताए जा रहे हैं,इसके बावजूद अब अचानक समूह बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है,जिससे स्कूल परिसर में असमंजस और तनाव की स्थिति बन गई है।

शिकायतें विफल,अब 'स्थानीय बनाम बाहरी' का मुद्दा

बताया जा रहा है कि पहले वर्तमान समूह को हटाने के लिए लगातार शिकायतें कराई गईं। प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा जांच भी की गई, लेकिन जांच में समूह को क्लीन चिट मिल गई, इसके बाद अब नया स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा खड़ा किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिसे बाहरी बताया जा रहा है,वह समूह भी स्थानीय लोगों द्वारा ही संचालित है।

एक ही समूह को लाभ क्यों?

पूरे मामले में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि स्थानीयता ही आधार है,तो फिर अन्य स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं किया गया? केवल एक खास समूह, जो राजनीतिक दल के एक कार्यकर्ता से जुड़ा बताया जा रहा है,उसी का नाम क्यों प्रस्तावित किया जा रहा है? सूत्रों का कहना है कि अन्य समूहों को न तो सूचना दी गई और न ही किसी चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया।

लेनदेन और दबाव की चर्चाएं...

मामले में बड़े लेनदेन की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक,शिकायतों से बात नहीं बनी तो शाला प्रबंधन समिति पर दबाव बनाया गया और इसके बाद ही आनन-फानन में बैठक बुलाकर नया प्रस्ताव लाया गया,यदि यह आरोप सही हैं,तो यह योजना की पारदर्शिता और ईमानदारी पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

शिक्षकों में नाराजगी,विवाद की आशंका

सूत्रों के अनुसार,इस बेवजह बदलाव से स्कूल के शिक्षक भी नाराज बताए जा रहे हैं। नाम न छापने की शर्त पर शिक्षकों का कहना है कि वर्तमान समूह बेहतर ढंग से काम कर रहा है,शिक्षा सत्र समाप्ति की ओर है, ऐसे समय में बिना शिकायत बदलाव से कार्यक्रम प्रभावित होने की आशंका है,कई लोगों का मानना है कि यह जबरन बदलाव आगे चलकर विवाद और टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है।

बड़ा सवाल–पोषण या फायदा?

आत्मानंद विद्यालय पटना का यह मामला अब एक बड़े सवाल की ओर इशारा कर रहा है क्या मध्यान्ह भोजन योजना वास्तव में स्कूली बच्चों के पोषण के लिए है, या फिर यह राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की जेब भरने का जरिया बनती जा रही है? अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाते हैं या नहीं। बच्चों के पोषण से जुड़ी योजना पर राजनीति भारी पड़ी तो इसका खामियाजा सीधे स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ेगा।

स्थानीय बाहरी का ही यदि है मुद्दा,एक ही समूह का नाम क्यों आ रहा बाहर,अन्य समूहों को प्रकिया में क्यों नहीं किया जा रहा शामिल?

पूरे मामले में यह सवाल उठ रहा है कि यदि मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का बेहतर संचालन करने वाले किसी समूह को यदि बाहरी और स्थानीय मुद्दे पर ही हटाया जा रहा है तो फिर अन्य स्थानीय समूहों को भी प्रकिया में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है,केवल एक ही समूह का नाम क्यों प्रस्तावित किया जा रहा है,बताया जा रहा है एक खास समूह जो एक स्थानीय स्तर के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता का समूह है उसे ही यह जिम्मेदारी दिए जाने की तैयारी है अन्य स्थानीय समूहों को कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है कि संचालन समूह में बदलाव का कोई कार्य किया जा रहा है।

कलेक्टर पर गंभीर आरोप,प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंची शिकायत

पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने मांगी उच्चस्तरीय व निष्पक्ष जांच

गुलाब कमरों ने कलेक्टर एमसीबी के विरुद्ध की उच्च स्तरीय शिकायत

-राजन पाण्डेय-

एमसीबी, 10 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

जिले के प्रशासनिक महकमे को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। पूर्व विधायक एवं छत्तीसगढ़ ट्रेड यूनियन काउंसिल के प्रांताध्यक्ष गुलाब कमरो ने एमसीबी जिले के कलेक्टर पर गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाते हुए मामले को सीधे देश और प्रदेश के शीर्ष स्तर तक पहुंचा दिया है,गुलाब कमरो ने इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्मिक,लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,नई दिल्ली,छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को विस्तृत शिकायती पत्र प्रेषित कर उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है।

बड़ा सवाल

क्या शासन इस गंभीर शिकायत को केवल औपचारिकता तक सीमित रखेगा,या फिर प्रशासनिक जवाबदेही तय कर कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगा? नज़रें अब शासन के अगले कदम पर टिकी हैं।

पद के दुरुपयोग और दमनात्मक कार्रवाई के आरोप

शिकायती पत्र में पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि कलेक्टर,जिला एमसीबी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध नियमविरुद्ध,एकतरफा और दमनात्मक कार्यवाही की गई। यह कार्रवाई न केवल शासकीय सेवा नियमों का उल्लंघन है,बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों के भी खिलाफ है।

शिकायत में लगाए गए प्रमुख आरोप

गुलाब कमरो ने अपनी शिकायत में कलेक्टर पर निम्न गंभीर आरोप लगाए हैं शासकीय कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से मानसिक रूप से प्रताड़ित करना,कार्यालय परिसर में पुलिस बल बुलाकर भय और दबाव का माहौल बनाना,कर्मचारियों को कलेक्टर कार्यालय में जबरन बैठाकर रखना,शासन के नियमों के विरुद्ध बिना सुनवाई एकतरफा निलंबन आदेश जारी करना।

हड़ताल समर्थन के दौरान का पूरा घटनाक्रम

शिकायत के अनुसार, दिनांक 30 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी/अधिकारी फेडरेशन (एस.सी.सी.) के पदाधिकारी गोपाल सिंह (व्यायाम शिक्षक), सुरेन्द्र प्रसाद (सफाई कर्मचारी) एवं संजय पाण्डेय (राजस्व निरीक्षक) तीन दिवसीय आंदोलन के दूसरे दिन हड़ताल के समर्थन में कलेक्टर कार्यालय,मनेंद्रगढ़ पहुंचे थे,गुलाब कमरो का स्पष्ट आरोप है कि संबंधित कर्मचारियों ने किसी भी प्रकार का दबाव, दुर्व्यवहार या अमर्यादित आचरण नहीं किया,बल्कि शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में कर्मचारियों से स्वेच्छा से आंदोलन में सहयोग का अनुरोध किया था इसके बावजूद कलेक्टर द्वारा पुलिस बल बुलाकर कर्मचारियों को लंबे समय तक बैठाए रखने,बाद में थाने ले जाकर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने जैसे कदम उठाए गए,जो पूरी तरह अलोकतांत्रिक और दमनकारी हैं।

बिना नोटिस निलंबन पर गंभीर सवाल

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित कर्मचारियों को न तो कारण बताओ नोटिस दिया गया,न ही पूर्व सूचना दी गई,और न ही पक्ष रखने का अवसर दिया गया,इसके बावजूद एकतरफा निलंबन आदेश जारी कर दिए गए,जबकि संबंधित कर्मचारी एक मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी भी हैं। पूर्व विधायक ने इसे स्पष्ट रूप से नियमविरुद्ध बताया है।

पूर्व मामलों का हवाला देकर सवाल

गुलाब कमरो ने अपने शिकायती पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि इससे पहले संजय पाण्डेय के एक समान प्रकरण में निलंबन को निरस्त करते हुए निलंबन अवधि को कार्यावधि मानकर प्रकरण समाप्त किया जा चुका है, यह तथ्य पहले ही ऐसे निलंबन आदेशों की तथ्यहीनता और दुर्भावना को उजागर करता है।

उच्चस्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग...

पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने मांग की है कि कलेक्टर,जिला एमसीबी द्वारा की गई समस्त कार्यवाहियों की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, दोष सिद्ध होने पर कलेक्टर के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए,ताकि शासकीय कर्मचारियों को न्याय मिल सके और भविष्य में इस प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई की पुनरावृत्ति न हो।

जिले के आस पास के क्षेत्रों मे हाथियों के पहूंचने से ग्रामीणों मे दहशत

-संवाददाता-

कोरबा, 10 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

कोरबा जिलान्तर्गत कटघोरा वन मंडल के जटगा रेंज में घूम रहा,वहीँ दंतैल हाथी चैतुरगढ़ पहाड़ी पर पहुंच गया है। कोरबा वन मंडल में हाथियों की संख्या 14 हो गई है। तीन हाथी धरमजयगढ़ वनमंडल से कुदमुरा रेंज पहुंचे हैं। वन विभाग ने आसपास गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है की ग्रामीण जंगल की ओर न जाए। पाली रेंज के रतखंडी,पहाड़गांव,जेमरा में लंबे समय बाद दंतैल हाथी के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने सुबह जंगल के बीच खेत में हाथी के पद चिन्ह देखे जाने पर वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग ने पुष्टि करने के बाद आसपास के गांवों में लोगों को सतर्क रहने मुनादी कराई है। कटघोरा वन मंडल में 53 से अधिक हाथी घूम रहे हैं,इनमें से दंतैल हाथी झुंड से अलग होकर घूम रहा है। कुदमुरा रेंज में पहुंचे तीन हाथी दंतैल हैं।

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर ,जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

रा0प्र0क्र0 202411020700120/ अ-27/ 2024-25

फर्द बटवारा का अंतिम प्रकाशन

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय के रा0प्र0क्र0 202411020700120/अ-27/2024-25 पक्षकार महमुद आलम प्रति अराबियुन निशा वगै. में ग्राम अम्बिकापुर स्थित खसरा नंबर 2512 / 2, 2517/1 रकवा क्रमशः 0.010 0.120 हे. भूमि का फर्द बंटवारा सूची हल्का पटवारी से प्राप्त हुआ है, जिसका अंतिम प्रकाशन कराया जा रहा है । अतः उक्त फर्द बंटवारा में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 30/01/2026 को न्यायालय में स्वय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 15/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

तहसीलदार
अम्बिकापुर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दरिमा ,जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

रा0प्र0क्र0 .../ब-121/ 2025

ईश्तहार /उद्घोषण

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि ग्राम -नावापारा कला थाना व तहसील दरिमा को सूचित किया जाता हैं। कि आवेदक / आवेदिका श्री / श्रीमती चिंगरू लाल रजक पिता स्व0 सोटलूराम निवासी ग्राम नावापारा कला थाना व तहसील दरिमा जिला सरगुजा, छ0ग0 के द्वारा उनके पिता स्व0 सोटलूराम की मृत्यु दिनांक 12/03/2003 अपने निवास स्थान ग्राम नावापारा कला में हुआ है।

इस संबंध में किसी व्यक्ति को कोई दावा / आपत्ति हो तो लिखित में स्वयं या अपने अधिवक्ता के द्वारा दावा / आपत्ति दिनांक 23/ 1 / 2026 तक प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा / आपत्ति पर सुनवाई हेतु विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 9/01/ /2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

कार्यपालिक दण्डाअधिकारी
दरिमा
जिला सरगुजा (छ0ग0)

मोबाइल हाजिरी पर सरकार सख्त

निजी डेटा सुरक्षा को लेकर कर्मचारी चिंतित

ऑनलाइन हाजिरी लागू, जुगाड़ की आशंका और विरोध तेज

हाजिरी के नाम पर दबाव? कर्मचारियों ने उठाए निजता के सवाल

ऑनलाइन हाजिरी की जिद या निजता पर वार? कर्मचारी संगठनों का विरोध

हाजिरी ऐप से डर, बायोमैट्रिक की मांग—सरकार बनाम कर्मचारी

सरकार की मंशा अनुशासन और जवाबदेही...

सरकार का दावा है कि मोबाइल आधारित ऑनलाइन हाजिरी से कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित होगी,कार्यालय समय में अनुशासन आएगा,और कार्य अवधि के दौरान अनावश्यक गैरहाजिरी पर रोक लगेगी,इसी उद्देश्य से सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि कर्मचारी अपने व्यक्तिगत मोबाइल फोन में हाजिरी ऐप डाउनलोड कर नियमित उपस्थिति दर्ज करें। कई जिलों में प्रशासन इसे उपलब्धि के रूप में सोशल मीडिया पर प्रचारित भी कर रहा है।

कर्मचारी संगठनों का रुख—हाजिरी से नहीं,निजी मोबाइल से आपत्ति

कर्मचारी संघों का कहना है कि उन्हें ऑनलाइन हाजिरी की अवधारणा से आपत्ति नहीं है, लेकिन वे व्यक्तिगत मोबाइल फोन के इस्तेमाल का विरोध कर रहे हैं,संघों की प्रमुख मांगें हैं कार्यालयों में पृथक बायोमैट्रिक मशीन लगाई जाए, या हाजिरी के लिए सरकारी डिवाइस/टैबलेट उपलब्ध कराया जाए, ताकि कर्मचारियों की निजता और व्यक्तिगत संसाधनों पर बोझ न पड़े।

निजी डेटा लीक होने का डर

कर्मचारी संगठनों ने सबसे गंभीर सवाल डेटा सुरक्षा को लेकर उठाया है। उनका कहना है कि जिस ऐप के माध्यम से हाजिरी ली जा रही है, उसकी साइबर सुरक्षा और प्रमाणिकता को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी साझा नहीं की गई है, यदि ऐप के कारण कर्मचारियों का व्यक्तिगत डेटा, बैंकिंग जानकारी या अन्य संवेदनशील सूचनाएं लीक होती हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मौजूदा व्यवस्था में जवाबदेही तय नहीं है, कर्मचारियों का तर्क है कि आज मोबाइल फोन केवल संपर्क का साधन नहीं, बल्कि डिजिटल भुगतान, बैंकिंग, निजी दस्तावेज और पारिवारिक सूचनाओं का केंद्र है, ऐसे में किसी अप्रमाणित ऐप को मजबूरी में डाउनलोड करना आर्थिक और साइबर सुरक्षा दोनों के लिहाज से जोखिमपूर्ण है।

प्रशासन का दबाव, बढ़ती असंतुष्टि

सरकार के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन स्तर पर कर्मचारियों पर ऐप डाउनलोड करने का दबाव साफ दिखाई दे रहा है, कई कर्मचारी अनिच्छा के बावजूद मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह प्रक्रिया स्वैच्छिक नहीं, बल्कि दबाव आधारित है, वहीं प्रशासन इसे नियमों के पालन और अनुशासन की दिशा में जरूरी कदम बता रहा है।

-रवि सिंह-

कोरिया/एमसीबी,10 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों की कर्तव्यस्थल पर दैनिक उपस्थिति और कार्य अवधि की निगरानी के लिए लागू की जा रही ऑनलाइन मोबाइल हाजिरी व्यवस्था अब प्रशासनिक निर्णय से आगे बढ़कर विवाद,विरोध और बहस का विषय बन गई है,सरकार जहां इस प्रणाली को सख्ती से लागू करने पर अड़ी हुई है, वहीं कर्मचारी संगठनों में इसे लेकर विरोध, सीमित समर्थन और वैकल्पिक मांगें सामने आ रही हैं,इसी बीच इस व्यवस्था में 'जुगाड़' की संभावनाओं को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।

'जुगाड़' की चर्चाएं—व्यवस्था पर ही सवाल

इस पूरी व्यवस्था में एक और पहलू सामने आ रहा है 'जुगाड़' की संभावनाएं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन चर्चाओं के अनुसार कुछ कर्मचारी पुराने नंबर की जगह नया मोबाइल नंबर कार्यालय रिकॉर्ड में दे रहे हैं,उस नंबर वाला मोबाइल दिनभर कार्यालय में छोड़ दिया जाता है,और कर्मचारी इस दौरान बाहर आ-जा सकते हैं,शाम को वही मोबाइल वापस ले लिया जाता है,यदि ऐसी स्थिति वास्तव में सामने आती है,तो यह ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था के मूल उद्देश्य वास्तविक उपस्थिति और कार्य समय सुनिश्चित करने को ही कमजोर कर देती है।

सीमित समर्थन भी मौजूद

कुछ कर्मचारियों का मानना है कि यदि ऐप पूरी तरह सुरक्षित,सरकारी स्तर पर प्रमाणित,और डेटा सुरक्षा की स्पष्ट गारंटी के साथ लागू किया जाए,तो ऑनलाइन हाजिरी से प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हो सकता है,हालांकि यह समर्थन भी निजी मोबाइल की जगह सरकारी व्यवस्था की शर्त के साथ जुड़ा हुआ है।

बड़ा सवाल अब भी कायम

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार कर्मचारियों की निजता और डेटा सुरक्षा को लेकर ठोस भरोसा दे पाएगी? क्या बायोमैट्रिक या वैकल्पिक प्रणाली पर गंभीरता से विचार होगा? या फिर यह ऑनलाइन मोबाइल हाजिरी व्यवस्था विरोध,असंतोष और 'जुगाड़' को जन्म देती रहेगी? स्पष्ट है कि ऑनलाइन मोबाइल हाजिरी केवल एक तकनीकी कदम नहीं रह गया है,बल्कि यह अब कर्मचारी अधिकार,विश्वास और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है।

धान खरीदी में अव्यवस्था पर पूर्व विधायक गुलाब कमरो का हमला,बोले...दमनात्मक कार्रवाई से किसान बेहाल

-संवाददाता-

एमसीबी,10 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

जिले में धान खरीदी को लेकर प्रशासन और किसानों के बीच बढ़ते तनाव के बीच गुलाब कमरो ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि प्रशासन की गलत नीतियों और दमनात्मक कार्रवाई के कारण जिले भर के किसान भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

गुलाब कमरो ने कहा कि किसान कड़ी मेहनत से उपजाई गई अपनी धान की फसल को समितियों में बेचने के लिए मजबूरन इधर-उधर भटक रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अव्यवस्था और दबावपूर्ण निर्णयों के चलते धान खरीदी सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षमता के अनुरूप धान का उठाव नहीं होने से समितियों में भारी मात्रा में स्टॉक जमा हो गया है। पूर्व विधायक के अनुसार, धान उठाव प्रभावित होने से कई समितियां जाम की स्थिति में पहुंच गई हैं। इसका सीधा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें कई-कई दिनों तक अपनी उपज लेकर इंतजार करना पड़ रहा है। कई जगह हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि धान खरीदी को अस्थायी रूप से रोकना पड़ रहा है, उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई किसानों की समस्याओं को कम करने के बजाय और अधिक बढ़ा रही है, गुलाब कमरो ने जिला प्रशासन से मांग की कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और तत्काल प्रभाव से ठोस समाधान निकाला जाए, ताकि धान खरीदी व्यवस्था पटरी पर लौट सके, पूर्व विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो किसानों का आक्रोश और तेज हो सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

राम वन गमन पथ पर 'विकास' नहीं, विनाश की पटकथा

हरचौका से कुँवारपुर तक रेत माफिया बेलगाम,प्रशासनिक संरक्षण के गंभीर आरोप

-राजन पाण्डेय-

भरतपुर,10 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

आस्था, संस्कृति और विकास के प्रतीक के रूप में विकसित किए जा रहे राम वन गमन पथ पर इन दिनों विकास के बजाय विनाश की काली इबारत लिखी जा रही है। जनकपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हरचौका से लेकर कुँवारपुर के पटवाही तक अवैध रेत उत्खनन का काला कारोबार खुलेआम फल-फूल रहा है। स्थिति यह है कि नदियों का सीना दिन-रात भारी मशीनों से चीरा जा रहा है,लेकिन जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठे हैं।

कुँवारपुर पटवाही में वन विभाग कटघरे में...

मामला यहीं नहीं रुकता। कुँवारपुर के पटवाही क्षेत्र में तो स्थिति और भी गंभीर बताई जा रही है। संरक्षित वन क्षेत्र से ट्रैक्टरों द्वारा खुलेआम रेत का उत्खनन और भंडारण किया जा रहा है, ग्रामीणों का आरोप है कि पूरे इलाके में एक ही व्यक्ति को अवैध उत्खनन और परिवहन की खुली छूट है, वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी मौन हैं, और इस पूरे नेटवर्क के पीछे किसी प्रभावशाली नेता जी की छत्रछाया बताई जा रही है,यह हालात सीधे-सीधे वन विभाग की भूमिका को संदेह के घेरे में खड़ा करते हैं।

सवाल जस का तस

क्या आस्था के इस पवित्र मार्ग को रेत माफियाओं के हवाले छोड़ दिया जाएगा? या फिर प्रशासन अब नींद से जागकर कार्रवाई करेगा? जनता जवाब चाहती है—और वो भी अब।

आस्था के मार्ग पर 'काली कमाई' का खेल

जिस पथ को भगवान श्रीराम के वनवास काल से जोड़कर धार्मिक पर्यटन और स्थानीय विकास का आधार बनाया गया, वही मार्ग अब रेत माफियाओं के लिए तस्करी का कॉरिडोर बनता जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार हरचौका धार्मिक स्थल के समीप मवई नदी से सैकड़ों गाड़ियों में अवैध रूप से रेत निकाली जा रही है। पोकलेन और जेसीबी जैसी भारी मशीनें बिना किसी डर के नदी में उतारी गई हैं।

रात होते ही तेज होता है उत्खनन

स्थानीय निवासियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जैसे ही सूर्य अस्त होता है, अवैध उत्खनन और अधिक आक्रामक हो जाता है,नियमों की धज्जियां पर्यावरणीय स्वीकृति,खनन सीमा और समय सबकी खुलेआम अनदेखी, ओवरलोड परिवहन क्षमता से अधिक लदे ट्रक और ट्रैक्टर दिन-रात दौड़ रहे हैं, सड़कें बर्बाद करोड़ों रुपये की लागत से बनी नई सड़कें कुछ ही महीनों में जर्जर हो चुकी हैं।

पर्यावरण और भविष्य पर सीधा हमला

अवैध रेत उत्खनन का असर केवल सड़क या नदी तक सीमित नहीं है,भूजल स्तर गिरता जा रहा है, जलीय जीव-जंतुओं का अस्तित्व खतरे में,बरसात में कटाव और बाढ़ का खतरा बढ़ा,और आसपास के खेतों व आबादी पर भी संकट मंडरा रहा है।

प्रशासनिक चुप्पी, संरक्षण के आरोप

सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस, राजस्व और खनन विभाग की जानकारी के बिना यह सब कैसे संभव है? ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि माफियाओं को स्थानीय राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है। शिकायतें दी गईं, मौखिक सूचनाएं भी पहुंचीं,लेकिन न तो छापे पड़े,न मशीनें जब्त हुईं,न कोई बड़ी कार्रवाई।

जनता की मांग,अब सिर्फ आश्वासन नहीं, कार्रवाई

क्षेत्र की जनता,सामाजिक संगठनों और पर्यावरण प्रेमियों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि...

- अवैध रेत उत्खनन पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए...
- पोकलेन, जेसीबी, ट्रक ट्रैक्टर जब्त कर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो...
- दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए...
- राम वन गमन पथ की गरिमा,पर्यावरण और धार्मिक महत्व को संरक्षित किया जाए...

सीईओ ने ग्राम पंचायत केराझरिया में आजीविका सेवा केंद्र का किया शुभारंभ

लखपति दीदी लक्ष्य की ओर कोरबा जिले की मजबूत पहल

-संवाददाता-

कोरबा,10 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

जिला पंचायत कोरबा के सीईओ दिनेश नाग ने विकासखंड पाली की ग्राम पंचायत केराझरिया में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत एकीकृत कृषि संकुल योजना के तहत स्थापित आजीविका सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीईओ श्री नाग ने कहा कि आजीविका सेवा केंद्र ग्रामीण महिलाओं एवं स्व-सहायता समूहों के लिए एक ही स्थान पर आजीविका से जुड़ी सभी आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम बनेगा। इससे कृषि, पशुपालन, गैर-कृषि उद्यम एवं स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीण परिवारों की आय में सतत वृद्धि सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि यह केंद्र किसानों और महिला समूहों को तकनीकी मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण इनपुट, प्रशिक्षण, उपकरण सुविधा एवं बाजार से जोड़ने में सहायक होगा। यह पहल ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ लखपति दीदी लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कार्यक्रम में जिला मिशन प्रबंधक अनुराग जैन ने आजीविका सेवा केंद्र की अवधारणा स्पष्ट करते हुए बताया कि यह केंद्र खेती, पशुपालन,मत्स्य पालन,गैर-कृषि एवं सूक्ष्म उद्यमों से संबंधित सेवाएँ, जानकारी और संसाधन उपलब्ध कराएगा,जिससे ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका को टिकाऊ बना सकें और आर्थिक रूप से सशक्त हों। उन्होंने बताया कि केंद्र के प्रमुख उद्देश्यों में ग्रामीण गरीबों की आय बढ़ाना,तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, इनपुट,प्रशिक्षण एवं बाजार तक आसान पहुँच सुनिश्चित करना तथा स्थानीय उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देना शामिल है।

कार्यक्रम में सरपंच,जनपद पंचायत प्रतिनिधि श्री सत्यनारायण पैकरा,बिहान मिशन के अधिकारी-कर्मचारी,स्व-सहायता समूहों की महिलाएँ तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

भयंकर ठंड में बिना कपड़ों के पेड़ पर क्यों चढ़े विद्युत जामवाल? वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी

बॉलीवुड एक्टर का एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वे बिना कपड़ों के पेड़ पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्यों एक्टर ने भरी ठंड में ये स्टंट किया? विद्युत जामवाल को उन अभिनेताओं में गिना जाता है जो फिटनेस के लिए हमेशा अवेयर रहते हैं और उनकी फिटनेस दूसरों को भी काफी इंस्पायर करती है। अब हाल ही में विद्युत का एक ऐसा वीडियो वायरल हो गया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। दरअसल इस वीडियो में विद्युत बिना कपड़ों के पेड़ पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।

क्यों बिना कपड़ों के पेड़ पर चढ़े विद्युत

विद्युत ने इस वीडियो को शेयर करते हुए खुद ही इसके पीछे की वजह बताई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर वीडियो शेयर किया और कैप्शन लिखा, %एक कलरिपयट्टू प्रैक्टिशनर के तौर पर, मैं साल में एक बार सहज योग का अभ्यास करता हूं। सहज का मतलब है प्राकृतिक सहजता और सहज प्रवृत्ति की स्थिति में लौटना, जिससे प्रकृति और अंदरूनी जागरूकता से गहरा जुड़ाव बनता है। वैज्ञानिक रूप से, यह कई न्यूरोरिसेप्टर्स और प्रोप्रियोसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, जिससे सेंसरी फीडबैक बेहतर होता है और बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में सुधार होता है। इससे शरीर के बारे में ज़्यादा जागरूकता, मानसिक फोकस बढ़ता है और ज़मीन से जुड़ाव का गहरा एहसास होता है।

वेजिटेरियन हैं विद्युत जामवाल

विद्युत जामवाल अक्सर योग और प्राणायम की पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं वहीं वे कभी-कभी अपनी डाइट से संबंधित पोस्ट भी शेयर करते हैं। विद्युत को इंडस्ट्री के सबसे फिट एक्टर्स में से एक माना जाता है और वे समय-समय पर इस बात को साबित भी करते हैं। वे कई सालों से शाकाहारी हैं। वह उन सेलेब्स में से हैं जो जानवरों के अधिकारों का सपोर्ट करते हैं। पहले उन्हें पेटा का सबसे हॉट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी चुना गया था। जामवाल अपने प्लांट-बेस्ड लाइफस्टाइल को अपनी फुर्ती और तेजी का श्रेय देते हैं, जिससे उन्हें कलरिपयट्टू की मुश्किल फिजिकल ट्रेनिंग में फायदा होता है।

कौन है हुसैन उस्तरा जिसके रोल में नजर आएंगे शाहिद कपूर

टीजर रिलीज के बाद लोग ढूंढ़ रहे कहानी

विशाल भारद्वाज की फिल्म ओ रोमियो का फर्स्ट लुक टीजर जारी हो गया है,जिसमें शाहिद कपूर का गुस्सैल अंदाज कबीर सिंह और कमीने की याद दिला रहा है। यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित बताई जा रही है और फैंस का मानना है कि यह सपना दीदी,हुसैन उस्तरा और दाऊद इब्राहिम की वास्तविक गैंगस्टर कहानी पर आधारित है।

विशाल भारवाज की फिल्म ओ रोमियो का मचअवेटेड फर्स्ट लुक टीजर रिलीज हो गया है। शाहिद कपूर के गुस्सैल रूम ने सभी का ध्यान खींचा। कुछ का कहना है कि वो कबीर सिंह के दौर में वापस चले गए हैं जबकि कुछ का मानना है कि उनमें कमीने जैसा वहीं पागलपन नजर आ रहा है।हर कोई टीजर की खूब तारीफ कर रहा है। वहीं प्रोमो में फिल्म निर्माताओं ने दावा किया है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। वहीं कुछ फैंस का मानना है कि यह फिल्म सपना दीदी, हुसैन उस्तारा और दाऊद इब्राहिम की असल जिंदगी की गैंगस्टर कहानी पर आधारित है। टीजर देखने के बाद वो इसपर कमेंट कर रहे हैं।

यूजर्स ने की शाहिद की तुलना

एक यूजर ने ट्वीट किया,तो शाहिद हुसैन उस्तरा का किरदार निभा रहे हैं,जो दाऊद इब्राहिम का प्रतिद्वंदी है। तृप्ति सपना दीदी का किरदार निभा रही हैं, जिनके पति की हत्या इब्राहिम ने की थी। वह उसके खिलाफ उस्तरा के साथ मिल जाती हैं। उन्होंने हत्या के कई प्रयास किए,लेकिन असफल रहीं,जिसके चलते दाऊद के आदमियों के हाथों उनकी मौत हो गई। इतने प्रतिभाशाली कलाकारों को देखते हुए फिल्म धमाकेदार होने की उम्मीद है! एक महिला जो अपने पति की हत्या के बाद दाऊद से बदला लेना चाहती है...हुसैन सपना दीदी के साथ साझेदारी करता है, लेकिन जब वे दाऊद और उसकी कंपनी को बाधित करने की कोशिश करते हैं तो सपना दीदी की हत्या कर दी जाती है।

एक अन्य ने लिखा, विशाल भारद्वाज की फिल्म ओ रोमियो में तृप्ति डिमरी का सपना दीदी के रूप में पहला लुक। वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं और लगता है उनका किरदार दमदार होगा। ओ रोमियो 13 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। यह फिल्म आदर्श गौरव और शनाया कपूर की मूवी तू या मैं से बॉक्स ऑफिस पर सीधी टक्कर लेने वाली है।

कौन हैं हुसैन उस्तरा

हुसैन उस्तरा मुंबई का एक गैंगस्टर था,जो दाऊद इब्राहिम के साथ अपनी दुश्मनी के लिए जाना जाता था। उस्तरा का असली नाम हुसैन शेख था। हिंसक लड़ाई करने की वजह से उसे उस्तारा नाम दिया गया। उन्होंने अपने दुश्मन के शरीर पर एक लंबा घाव कर दिया था।

हाथों में बंदूक लेकर लौट रही 90 के दशक की ये सुंदर सुशील हीरोइन

तीसरे पार्ट की रिलीज डेट का किया ऐलान

यश राज फिल्म्स की मर्दानी हिंदी सिनेमा की उन गिनी-चुनी महिला प्रधान फ्रेंचाइजी में से एक है, जिसने एक दशक से भी अधिक समय से दर्शकों का प्यार और प्रशंसा बटोरी है। भारत की सबसे बड़ी और इकलौती महिला पुलिस फ्रेंचाइजी मर्दानी ने अपने तीसरे पार्ट मर्दानी 3 के साथ प्रवेश किया, जिसमें रानी मुखर्जी ने दिलेर पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय की भूमिका निभाई है। फिल्म फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी की घोषणा शारदीय नवरात्रि 2025 के पहले दिन की गई थी। हालांकि, रिलीज की तारीख 27 फरवरी, 2026 घोषित की गई थी। लेकिन अब निर्माताओं ने महीने में सही अवसर को देखते हुए फिल्म की रिलीज को पहले करने का फैसला किया है।

मर्दानी 2 की नई रिलीज तिथि

आज, यश राज फिल्म्स (वाईआरएफ) ने मर्दानी 3 की रिलीज तिथि में बदलाव की घोषणा की है और अब यह 30 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी। इस फिल्म को शिवानी की अच्छाई और बुराई के बीच एक खूनी और हिंसक संघर्ष के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसमें वह देश की लापता लड़कियों की तलाश में समय के खिलाफ एक रोमांचक दौड़ में शामिल होती है। जब तक वह उन सभी को बचा नहीं लेती, तब तक वह रुकेगी नहीं! रानीमुखर्जी निडर पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में मर्दानी3 में वापसी कर रही हैं। बचाव अभियान 30 जनवरी से आपके नजदीकी सिनेमाघरों में शुरू हो रहा है,% निर्माताओं ने पहला पोस्टर साझा करते हुए लिखा।

खेल समाचार

गुजरात ने यूपी वॉरियर्ज को 10 रन से हराया

कप्तान एश्ले गार्डनर की फिफ्टी, अनुष्का ने 44 रन बनाए 3 बॉलर्स को 2-2 विकेट

नई दिल्ली,10 जनवरी 2026। गुजरात जायंट्स ने विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में जीत से शुरुआत की है। टीम ने शनिवार के पहले मुकाबले में यूपी वॉरियर्ज को 10 रन से हराया। पाटिल स्टेडियम में 208 रन का टारगेट चेज कर रही यूपी की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 197 रन ही बना सकी। फीबी लिचिफील्ड ने सबसे ज्यादा 78 रन बनाए। गुजरात के लिए रेणुका सिंह डीवाई ठाकुर, सोफी डिवाइन और जॉर्जिया वेयरहम ने 2-2 विकेट झटके। एक-एक विकेट कप्तान एश्ले गार्डनर और राजेश्वरी गायकवाड को मिला।

टॉस हारकर बैटिंग कर रही गुजरात ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 207 रन बनाए थे। जोकि गुजरात का सबसे बड़ा स्कोर है। कप्तान एश्ले गार्डनर ने 65 और अनुष्का शर्मा ने 44 रन बनाए। दोनों में 103 रन की पार्टनरशिप हुई। सोफी डिवाइन 38 रन बनाकर आउट हुईं। सोफी एक्लेस्टोन ने दो विकेट झटके।

विमेंस टी-20 में सबसे ज्यादा सिक्स का रिकॉर्ड बना

गुजरात-यूपी मैच में कुल 21 छक्के लगे हैं। जोकि विमेंस टी-20 के इतिहास में एक मैच में लगे सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड है। पिछला रिकॉर्ड 19 छक्कों का है। जोकि ड्डक्क्रू 2017ड्ड18 सीजन में सिक्सर्स बनाम स्टार्स और डब्ल्यूपीएल 2024 में आरसीबी व्हीएस डीसी मैचों में बना था।

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

गुजरात जायंट्स:- एश्ले गार्डनर (कप्तान),बेथ मूनी,सोफी डिवाइन, जॉर्जिया वेरेहम,अनुष्का शर्मा,भारती फुलमाली,कनिका आहूजा,काशवी गौतम,तनुजा कंवर,राजेश्वरी गायकवाड,रेणुका सिंह ठाकुर।

यूपी वॉरियर्स:- मेग लैनिंग (कप्तान),डिआंड्रा डॉटिन,फीबी लिचफील्ड,किरण नवगिरे,हरलीन देयोल,दीप्ति शर्मा,श्वेता सहरावत, सोफी एक्लेस्टोन,आशा सोभना, शिखा पांडे,क्रांति गौड़।

जम्मू-कश्मीर के कैंप से बाहर उमरान मलिक

नई दिल्ली,10 जनवरी 2026। तेज गेंदबाज उमरान मलिक को रणजी ट्रॉफी तैयारी कैंप के लिए जम्मू-कश्मीर की टीम से बाहर कर दिया गया है। इस कैंप का आयोजन पुडुचेरी में होगा। भारत के लिए 10 वनडे और 8 टी20 मैच खेल चुके उमरान मलिक रणजी ट्रॉफी के पहले हाफ में टीम का हिस्सा थे। उन्होंने श्रीनगर में राजस्थान के खिलाफ सिर्फ एक मुकाबला खेला, जिसमें कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 5 मुकाबलों में 6 विकेट हासिल करने वाले उमरान मलिक को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए टीम से बाहर कर दिया गया था। इनके अलावा, अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली के खिलाफ जम्मू-कश्मीर के लिए यादगार रणजी ट्रॉफी जीत में शतक लगाने वाले सलामी बल्लेबाज कामरान इकबाल को भी टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) ने दीक्षांत कुंडल और कवलप्रीत सिंह को टीम में शामिल किया है। इनके साथ उमर नजीर और शुभम पुंडीर भी टीम में वापस आ गए हैं। फिलहाल जम्मू-कश्मीर 5 मुकाबलों में 20 अंकों के साथ टेबल-टॉपर मुंबई के बाद एलीट ग्रुप डी में दूसरे स्थान पर है। यह टीम 22 जनवरी से पुडुचेरी के खिलाफ अपने रणजी ट्रॉफी चरण 2 अभियान की शुरुआत करेगी। यह मुकाबला सिचेम स्टेडियम में खेला जाना है, जिससे पहले 17 जनवरी को हेड कोच अजय शर्मा टीम से जुड़ेंगे। इसके बाद यह टीम 29 जनवरी से 1 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मुकाबला खेलेगी। नॉकआउट मैच 6-28 फरवरी के बीच आयोजित होंगे। टीम के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के सदस्य 16 जनवरी को जेकेसीए की व्यवस्था के तहत अपने-अपने स्थानों से सीधे चेन्नई जाएंगे। इसके बाद टीम चेन्नई से पुडुचेरी जाएगी। रणजी ट्रॉफी तैयारी शिविर के लिए जम्मू-कश्मीर टीमः- शुभम खजुरिया, दीक्षांत कुंडल, यावर हसन, पारस डोगरा, अब्दुल समद, शुभम पुंडीर, कन्हैया वाधावन, कवलप्रीत सिंह, आबिद मुश्ताक, वंशज शर्मा, साहिल लोतरा, औकिब नबी, युद्धवीर सिंह, उमर नजीर और सुनील कुमार।

मुंबई मैराथन ने अपने 21 वें एडिशन में कोस्टल रोड को शामिल किया

मुंबई,10 जनवरी 2026। टाटा मुंबई मैराथन ने अपने 21वें एडिशन के लिए एक ऐतिहासिक रूट का अनावरण किया है, जो रविवार, 18 जनवरी को होगा, जो इस इवेंट की शानदार विरासत में एक ऐतिहासिक पहली घटना है। एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, पहली बार, धावक मैराथन रूट के हिस्से के रूप में नए खुले मुंबई कोस्टल रोड का अनुभव करेंगे, साथ ही आइकॉनिक बांद्रा-वर्ली सी लिंक भी। आधुनिक मोबिलिटी और रोज़ाना की आवाजाही का पर्याय, कोस्टल रोड, रेस के दिन लोगों के लिए एक मैदान में बदल जाएगा, जो धावकों को अरब सागर और शहर के स्काईलाइन के बिना रुकावट वाले नज़ारे देगा और दुनिया की सबसे मशहूर शहरी मैराथनों में से एक में एक शानदार नया अध्याय जोड़ेगा।

रेस कैटेगरी:- शुरू और खत्म होने के पॉइंट्स एलीट मैराथन~ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से शुरू और खत्म होने वाली इस रेस में दुनिया के टॉप एथलीट कोस्टल रोड के साथ नए रूट पर खुद को परखेंगे। **एमेच्योर मैराथन:-** सीएसएमटी से शुरू होकर बॉम्बे जिमखाना के पास एमजी रोड पर खत्म होने वाला यह कोर्स लगातार प्रदर्शन और सहनशक्ति को पुरस्कृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो धावकों को एक संतोषजनक फिनिश देता है। **हाफ मैराथन और पुलिस कप:-** माहिम कॉज़वे पर माहिम रेती बंदर ग्राउंड से शुरू होकर ओसीएस चौकी पर खत्म होने वाली यह रेस प्रतिभागियों को दक्षिण मुंबई के कुछ सबसे आइकॉनिक हिस्सों से गुज़ारती है। ओपन 10 रन, सीनियर सिटिजन्स रन, और **ड्रीम रन:-** सीएसएमटी से शुरू होकर मेट्रो जंक्शन पर एमजी रोड पर खत्म होने वाली ये कैटेगरी जीवन के सभी क्षेत्रों से हज़ारों धावकों को एक साथ लाएंगी। **चैंपियंस विद डिसेबिलिटी रन:-** सीएसएमटी से शुरू और खत्म होने वाली यह कैटेगरी प्रतिभागियों को इवेंट के केंद्र में एक सहायक, सुलभ अनुभव प्रदान करती है। अनिल कुंभारे, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक), मुंबई ने टिप्पणी की, ÷मुंबई मैराथन 2026 के रूट में कोस्टल रोड को शामिल करके, हमारा लक्ष्य मुंबई को एक वैश्विक मंच पर उसके सबसे अच्छे रूप में पेश करना है। यह नया रूट मैराथन धावकों को एक अनोखा और सुंदर अनुभव देगा, साथ ही अन्य यात्रियों के लिए भी सुरक्षा और आवाजाही में आसानी सुनिश्चित करेगा। रूट की योजना व्यापक इंटरएजेंसी समन्वय के साथ बनाई गई है ताकि कुशल ट्रैफिक प्रबंधन, मज़बूत सुरक्षा तैनाती और निर्बाध संचालन सुनिश्चित किया जा सके, ताकि रेस के दिन भी मुंबई सुचारू रूप से काम करता रहे। रेस डायरेक्टर ह्यूग जोन्स ने कहा, एक रेस के तौर पर, पिछले दो दशकों में, हमारा मकसद धावकों को नए अनुभव देना रहा है। नई कोस्टल रोड को शामिल करने से, मुंबई मैराथन न सिर्फ इस शहर की तरक्की को दिखाती है, बल्कि पुराने रूट और उसके हमेशा बने रहने वाले आकर्षण का भी हिस्सा बनाए रखती है। नए रूट की घोषणा पर बोलते हुए, विवेक सिंह, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रोकैम इंटरनेशनल, ने कहा, मुंबई मैराथन ने हमेशा शहर की भावना को दिखाया है। 21वें एडिशन के लिए रेस रूट में मुंबई कोस्टल रोड को शामिल करना न सिर्फ मैराथन के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, बल्कि शहर की तरक्की के लिए भी एक जीत है। नया रूट शहर की विरासत को उसके आधुनिक बदलाव के साथ जोड़ता है, जिससे धावकों को सच में वर्ल्ड-क्लास अनुभव मिलता है।

लैनिंग बनी दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी

नवी मुंबई ,10 जनवरी 2026। यूपी वॉरियर्ज की कप्तान मेग लैनिंग ने एलिसे पेरी के 972 रनों के आंकड़े को पार करके महिला प्रीमियर लीग में दूसरी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गईं, जब उन्होंने शनिवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम में टूर्नामेंट के दूसरे मैच में गुजरात जायंट्स का सामना किया। लैनिंग ने 27 गेंदों में 30 रन की पारी खेलने के बाद कुल 981 रन बनाए हैं और वह मुंबई इंडियंस की ऑलराउंडर नेट साइवर-ब्रंट के कुल रनों से सिर्फ़ 50 रन पीछे हैं, जो 1031 रनों के साथ चार्ट में सबसे ऊपर हैं (2026 के मैच 1 के बाद)। साइवर-ब्रंट टूर्नामेंट में 1000 से ज़्यादा रन बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिसका श्रेय उनके शानदार 2025 के कैंपेन को जाता है, जिसमें उन्होंने इतिहास रचा था। इंग्लैंड की कप्तान, एमआई के विजयी डब्ल्यूपीएल 2025 कैंपेन के दौरान, एक ही सीज़न में 500 से ज़्यादा रन बनाने वाली पहली और एकमात्र क्रिकेटर बनीं। पिछला रिकॉर्ड पेरी के 347 रनों का था, जो उन्होंने अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विजयी डब्ल्यूपीएल2024 सीज़न के दौरान हासिल किया था। चल रहे 2026 सीज़न में लैनिंग और साइवर-ब्रंट के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों सीनियर खिलाड़ी टूर्नामेंट के सर्वकालिक शीर्ष रन बनाने वालों की सूची में नंबर 1 स्थान हासिल करने का लक्ष्य रखेंगी। ऑस्ट्रेलिया की लैनिंग, जो अब वॉरियर्ज की कप्तान हैं, डब्ल्यूपीएल के इतिहास में सबसे लगातार प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों में से एक रही हैं। उन्होंने पहले तीन सीज़न में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला, 27 मैचों में 952 रन बनाए, जिससे फ्रेंचाइजी को अब तक के तीनों डब्ल्यूपीएल सीज़न में फाइनल में पहुंचने में मदद मिली। उन्हें डब्ल्यूपीएल 2026 से पहले एमआई ने रिलीज़ कर दिया था और बाद में क्कवॉरियर्ज ने उन्हें खरीद लिया, जिन्होंने उन्हें मौजूदा सीज़न के लिए टीम का कप्तान नियुक्त किया। पेरी ने आरसीबी का प्रतिनिधित्व करते हुए डब्ल्यूपीएल के अपने लगातार तीसरे सीज़न का समापन 972 रनों के साथ किया। वह 2024 में फ्रेंचाइजी की विजयी दौड़ में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थीं। पेरी को डब्ल्यूपीएल 2026 से पहले टीम ने रिटेन किया था, लेकिन उन्होंने निजी कारणों से टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया। डब्ल्यूपीएल 2026 की शुरुआत 9 जनवरी को हुई और यह 5 फरवरी तक चलेगा, जिसका फाइनल मैच वडोदरा केस्टेडियम (कोटांबी) में खेला जाएगा।

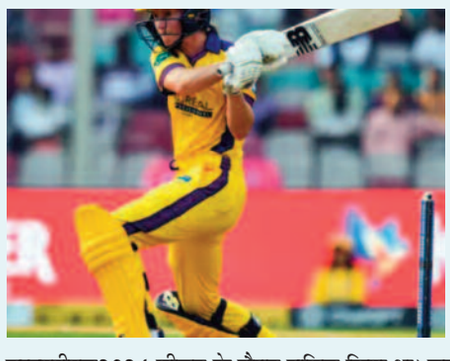

सेमीफाइनल में पीवी सिंधु की हार

क्वालालंपुर,10 जनवरी 2026। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु को शनिवार को चल रहे मलेशिया ओपन 2025 इवेंट में चीन की वर्ल्ड नंबर 2 वांग झीयी के खिलाफ महिला सिंगल्स सेमीफाइनल मैच में दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा। सिंधु कुआलालंपुर के स्टेडियम एक्सियाटा एरिना में वर्ल्ड नंबर 2 के खिलाफ सीधे सेटों में (21-16, 21-15) मैच हार गईं। पहला सेट काफी कड़ा था,जिसमें दोनों बेहतरीन खिलाड़ियों ने शुरुआती पलों में हर पॉइंट पर बराबरी की। हालांकि, सिंधु अपने नर्वस पर कंट्रोल नहीं रख पाईं,और गलतियों की वजह से झीयी ने 14-ऑल से 18-14 की बढ़त बना ली और पहला सेट जीत लिया। वर्ल्ड नंबर 2 झीयी ने दूसरे गेम में जल्दी ही बढ़त बना ली,लेकिन भारत की स्टार सिंधु ने वापसी करते हुए मिड-गेम इंटरवल में 11-6 की बढ़त ले ली। इंटरवल के बाद, सिंधु ने गलतियां करना शुरू कर दिया,जिससे चीनी शटलर को फिर से लय मिली,सेट खत्म किया और सीधे सेटों में मैच जीत लिया।

इससे पहले टूर्नामेंट में,भारत के लक्ष्य सेन गुरुवार को कुआलालंपुर के स्टेडियम एक्सियाटा एरिना में पुरुष सिंगल्स प्री-क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेउक यियू से हारने के बाद मलेशिया ओपन 2026 से बाहर हो गए। बैडमिंटन रैंकिंग में 13वें स्थान पर मौजूद लक्ष्य सेन हांगकांग, चीन के वर्ल्ड नंबर 18 ली चेउक यियू से 53 मिनट में 22-20, 21-15 से हार गए। 24 साल के भारतीय शटलर ने अच्छी शुरुआत की थी, इंटरवल में 11-9 से आगे थे और पहले गेम में चार गेम पॉइंट भी हासिल किए थे। हालांकि, ली चेउक यियू के लगातार छह पॉइंट्स ने बाजी पलट दी, और उन्होंने टाई-ब्रेक में पहला गेम जीत लिया। सेन वापसी नहीं कर पाए और दूसरा गेम भी हार गए। यह ली चेउक यियू के खिलाफ पांच मैचों में लक्ष्य सेन की तीसरी हार थी।

चावल निर्यातकों को दी बड़ी सौगात...मंडी शुल्क में छूट की अवधि एक साल बढ़ाई गई

ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है : सीएम साय

रायपुर,10 जनवरी 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शनिवार को राजधानी रायपुर के नीजि रिसॉर्ट में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने चावल निर्यातकों को बड़ी सौगात दी है। मंडी शुल्क में छूट की अवधि एक साल बढ़ाई है। इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट के दौरान सीएम साय ने की घोषणा से चावल निर्यातकों और किसान दोनों के लिए बड़ी सौगात है। साथ ही कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के क्षेत्रीय कार्यालय का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है और दंतेवाड़ा में ऑर्गेनिक चावल की खेती हो रही है, जिसे और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

छत्तीसगढ़ से चावल के एक्सपोर्ट को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट का यह दूसरा संस्करण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस आयोजन में 12 देशों के बायर्स तथा 6 देशों के एम्बेसी प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति से छत्तीसगढ़ को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने में मदद मिलेगी। उन्होंने छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर सभी विदेशी मेहमानों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने छत्तीसगढ़ को सोच-समझकर 'धान का कटोरा' कहा था और आज प्रदेश इस नाम की सार्थकता सिद्ध कर रहा है। चावल छत्तीसगढ़ के खानपान का अभिन्न हिस्सा रहा है और यहां हजारों किस्मों की धान की प्रजातियां उगाई जाती हैं। सरगुजा अंचल के सुगंधित जीराफूल और दुबराज जैसे चावलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी खुशबू दूर से ही पहचान में आ जाती है। छत्तीसगढ़ से चावल के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। चावल निर्यातक लंबे समय से मंडी शुल्क में छूट की मांग कर रहे थे। पिछले साल भी सरकार ने दी थी, छूट दिसंबर 2025 में मंडी शुल्क में छूट की अवधि खत्म हो रही थी।

छत्तीसगढ़ से 90 देशों को करीब एक लाख टन चावल का किया जा रहा है निर्यात

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे चावल के प्रसंस्करण और निर्यात को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से वर्तमान में लगभग 90 देशों को करीब एक लाख टन चावल का निर्यात किया जा रहा है। सरकार निर्यातकों के सहयोग के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। पिछले वर्ष 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी और इस वर्ष भी खरीदी में वृद्धि की संभावना है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र व राज्य शासन द्वारा किसानों के हित में संचालित योजनाओं की जानकारी भी साझा की।

मुख्यमंत्री ने चावल पर केन्द्रित प्रदर्शनी का किया अवलोकन

इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट के दौरान मुख्यमंत्री साय ने चावल पर केन्द्रित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न किस्मों के चावल,क्षेत्र विशेष में उत्पादित प्रजातियों, चावल उत्पादन में हो रहे नवाचारों तथा आधुनिक तकनीक के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने शासकीय स्टालों का भी निरीक्षण कर चावल के उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने से जुड़े कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे नवाचारों से चावल की पैदावार में वृद्धि होगी, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल,मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह,एपिडा के चेयरमेन अभिषेक देव,छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कांति लाल, राम गर्ग,देश भर से आये मिलर्स, चावल व्यवसायी एवं स्टेक होल्डर्स उपस्थित रहे।

पूर्व मुख्य सचिव अमिताभ जैन बने मुख्य सूचना आयुक्त

आईएएस उमेश कुमार,डॉ. शिरीष मिश्रा को सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी

रायपुर,10 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य सूचना आयोग में अहम नियुक्तियां करते हुए इसे और सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाया है। शासन ने पूर्व मुख्य सचिव अमिताभ जैन को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। उनके अनुभव और प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए यह नियुक्ति की गई है, जिससे सूचना आयोग की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता में और सुधार आने की उम्मीद है। साथ ही, राज्य सूचना आयोग में दो और सूचना आयुक्त के पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। इनमें सेवानिवृत्त आईएएस उमेश कुमार अग्रवाल और सीनियर पत्रकार डॉ. शिरीष चंद्र मिश्रा को शामिल किया गया है। दोनों ही नियुक्तियों से आयोग में प्रशासनिक और पत्रकारिता दृष्टिकोण का संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। उमेश कुमार अग्रवाल का प्रशासनिक अनुभव और डॉ. मिश्रा का मीडिया व जन संपर्क का अनुभव आयोग की कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायक साबित होगा।

नियुक्तियों की सभी प्रक्रिया और नियम तय

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इन सभी नियुक्तियों की सेवा शर्तें, वेतन और अन्य भत्ते भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर 2019 के तहत निर्धारित किए जाएंगे। यह अधिसूचना 'सूचना का अधिकार (केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोगों में पदावधि, वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2019' के अंतर्गत लागू होगी। इसके तहत नियुक्तियों की सभी प्रक्रिया और नियम तय किए गए हैं, ताकि आयोग में पारदर्शिता और सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके।

सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना मकसद : राज्य सूचना आयोग का काम जनता को सूचना का अधिकार प्रदान करना और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों से आयोग की भूमिका और प्रभावी होगी। इन नए नियुक्तियों के साथ उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य में सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त होने वाली याचिकाओं का निपटान तेजी से होगा और जनता को सरकारी नीतियों व निर्णयों के प्रति अधिक स्पष्ट जानकारी मिलेगी।

मनरेगा कानून में परिवर्तन केंद्र का मजदूर विरोधी कदम,राम जी के नाम पर झूठ बोल रही भाजपा : दीपक बैज

जगदलपुर,10 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जगदलपुर में कहा कि,मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का मजदूर विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है। मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है। केंद्र सरकार ने सुधार के नाम पर झांसा देकर लोकसभा में एक और बिल पास कर दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा को खत्म कर दिया है। यह महात्मा गांधी की सोच को खत्म करने और सबसे गरीब भारतीयों से काम का अधिकार छीनने की जान-बूझकर की गई कोशिश है। अब तक, मनरेगा संविधान के आर्टिकल 21 से मिलने वाले अधिकारों पर आधारित गारंटी थी। नया फ्रेमवर्क ने इसे एक कंडीशनल,केंद्र कंट्रोल की जाने वाली स्कीम में बदल दिया है। मनरेगा गांधीजी के ग्राम स्वराज,काम की गरिमा और डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट के सपने का जीता-जागता उदाहरण था।

12 करोड़ मनरेगा मजदूरों के अधिकारों को किया खत्म

लेकिन इस सरकार ने न सिर्फ उनका नाम हटा दिया है, बल्कि 12 करोड़ मनरेगा मजदूरों के अधिकारों को भी खत्म कर दिया। दो दशकों से मनरेगा करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए लाइफलाइन रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक सुरक्षा के तौर पर जरूरी साबित हुआ है। अब तक मनरेगा मजदूरों को काम देने का कानून था,श्रमिक अधिकार पूर्वक मांग करते जिसे योजना में परिवर्तित कर दिया गया। अब इसे चलाना नहीं चलाना सरकार की मर्जी पर निर्भर होगा। मनरेगा के तहत,सरकारी ऑर्डर से कभी काम नहीं रोका गया। नया सिस्टम हर साल तय टाइम के लिए जबरदस्ती रोजगार बंद करने की इजाजत देता है, जिससे राज्य यह तय कर सकता है कि गरीब कब कमा सकते हैं और कब उन्हें भूखा रहना होगा। एक बार फंड खत्म हो जाने पर, या फसल के मौसम में, मजदूरों को महीनों तक रोजगार से दूर रखा जा सकता।

अब केंद्र और राज्य का हिस्सा 60-40 का हो जाएगा...

दीपक बैज ने कहा कि, मनरेगा केंद्रीय कानून था। 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार भेजती थी। अब केंद्र और राज्य का हिस्सा 60 - 40 का हो जाएगा। पहले मैचिंग ग्रांट 50 प्रतिशत राशि राज्य जमा करेगी तब केंद्र सरकार राशि जारी करेगी। इस बिल से आने वाले समय में मनरेगा स्कीम खत्म हो जाएगी। जैसे ही बजट का बोझ राज्य सरकारों पर पड़ेगा,वैसे ही धीरे-धीरे मनरेगा बंद होने लगेगी। अब राज्यों पर जी राम जी का लगभग 50 हजार करोड़ का बोझ डालना चाहती है, उन्हें 40 प्रतिशत खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मनरेगा योजना देश के गरीब से गरीब लोगों के लिए रोजगार का सहारा थी, जो कोरोना जैसी मुश्किल हालातों में भी उनके साथ थी। इसलिए ये बिल गरीब मजदूरों के खिलाफ है। कांग्रेस ने कहा कि, 100 दिन से 125 दिन की मजदूरी वाली बात सिर्फ एक चालाकी है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 70 प्रतिशत गांव में भाजपा की सरकार आने के बाद से अघोषित तौर पर काम नहीं दिया जा रहा है। पिछले 11 सालों से भाजपा सरकार है, मनरेगा में काम देने का राष्ट्रीय औसत मात्र 38 दिनों का है। मतलब 11 साल में मोदी सरकार किसी भी साल 100 दिन काम नहीं दे पाई।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में प्रमोशन और नई पोस्टिंग

7 सहायक अभियंता बने असिस्टेंट इंजीनियर, अधिकारियों को मैट्रिक्स लेवल-12 पर मिलेगा वेतन

रायपुर, 10 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 7 उप अभियंता (सिविल) को पदोन्नति दी है। इन सभी को सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त किया गया है। पदोन्नति के बाद इन अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 के तहत 56,100 से 1,77,500 रुपए तक का वेतन मिलेगा। जारी आदेश के अनुसार, विनोद कुमार सिंह को कार्यालय सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उपखण्ड डोंगरगढ़ से लो.स्वा.यां. (सिविल), उपखण्ड राजनांदगांव रेवेन्द्र महोबिया को बालोद से पदोन्नति कर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड धमतरी ट्रांसफर किया गया है।

इन अधिकारियों को मिली पदोन्नति और नई पदस्थापना

- **प्रमोद कुमार महतो** - सहायक अभियंता, लो.स्वा.यां., उपखण्ड-1 बिलासपुर ? उपखण्ड चांपा स्थानांतरण।
- **डेमन लाल देशमुख** - सहायक अभियंता, लो.स्वा.यां., उपखण्ड नारायणपुर ? कार्यपालन अभियंता, खण्ड नारायणपुर पदोन्नति व पदस्थापना।
- **रूपचंद सूर्यवंशी** - सहायक अभियंता, लो.स्वा.यां., उपखण्ड कुरूद ? कार्यपालन अभियंता, खण्ड गरियाबंद पदोन्नति व पदस्थापना।
- **सत्यानारायण सिंह कंवर** - सहायक अभियंता, लो.स्वा.यां., उपखण्ड कोरबा (यथास्थान स्थानांतरण)।
- विमलेश कुमार सिंह - सहायक अभियंता, लो.स्वा.यां., उपखण्ड प्रतापपुर ? उपखण्ड वाड्रफनगर स्थानांतरण।
- **विनोद कुमार सिंह** - सहायक अभियंता, लो.स्वा.यां., उपखण्ड डोंगरगढ़ ? लो.स्वा.यां. (सिविल), उपखण्ड राजनांदगांव स्थानांतरण।
- **रेवेन्द्र महोबिया** - सहायक अभियंता, लो.स्वा.यां., उपखण्ड बालोद ? कार्यपालन अभियंता, खण्ड धमतरी पदोन्नति व पदस्थापना।

बिना सबूत अवैध संबंध का आरोप लगाना क्रूरता हाईकोर्ट ने डॉक्टर पति की तलाक याचिका स्वीकार की

बिलासपुर,10 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद के एक मामले में ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि बिना किसी ठोस सबूत के जीवनसाथी पर अवैध संबंधों का आरोप लगाना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस एके प्रसाद की बेंच ने इसी आधार पर एक डॉक्टर पति की तलाक की अर्जी स्वीकार कर ली है। मामला सारंगढ़ निवासी एक डॉक्टर का है, जिनका विवाह साल 2008 में भिलाई की रहने वाली एक महिला डॉक्टर से हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। पति का आरोप था कि पत्नी छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करती थी, मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने से इनकार करती थी और उस पर लगातार चरित्रहीन होने के झूठे आरोप लगाती थी।

फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दी थी अर्जी : पति ने पहले दुर्ग के फैमिली कोर्ट में

तलाक के लिए आवेदन किया था, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान पता चला कि पत्नी ने लिखित बयान में पति का संबंध एक अन्य महिला डॉक्टर से होने का गंभीर आरोप लगाया था, जिसे वह साबित नहीं कर पाई।

हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा एक शिक्षित पत्नी द्वारा पति पर बिना आधार के अवैध संबंधों का आरोप लगाना क्रूरता का सबसे वीभत्स रूप है। पत्नी पति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में नाकाम रही, जिससे पति को भारी मानसिक वेदना झेलनी पड़ी। कोर्ट ने पाया कि अप्रैल 2019 में दोनों साथ में फिल्म देखने गए थे, इसलिए केवल अलग रहने के आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता था, लेकिन 'क्रूरता' के आधार पर तलाक जायज है।

25 लाख रुपये गुजारा भत्ता का आदेश

अदालत ने तलाक की डिक्री मंजूर करते हुए पति को आदेश दिया है कि वह अपनी पत्नी को 25 लाख रुपये का एकमुश्त गुजारा भत्ता दे। चूंकि दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं और आर्थिक रूप से सक्षम हैं, फिर भी बेटी की परवरिश और भविष्य की कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए कोर्ट ने यह राशि 6 महीने के भीतर देने का निर्देश दिया है।

रक्षक ही बना भक्षक...डायल 112 चालक पर गैंगरेप का आरोप,5 में से 2 हिरासत में...

कोरबा,10 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से कानून-व्यवस्था को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बांकीमोंगरा थाना क्षेत्र में डायल 112 वाहन में तैनात चालक पर अपने चार साथियों के साथ मिलकर एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। मामला उजागर होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आरोपी चालक युवती को बहाने से बांकीमोंगरा स्थित एसईसीएल के एक मकान में ले गया,जहां साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई

और युवती को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोरबा में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं। इस सनसनीखेज मामले में सिविल लाइन थाना में अपराध दर्ज कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार,पांच आरोपियों में से दो को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है,जबकि तीन अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।

नेशनल जंबूरी की व्यवस्थाओं से खुश हुए स्काउट-गाइड के मुख्य राष्ट्रीय कमिश्नर,कहा...छत्तीसगढ़ ने एक महीने के भीतर की बेहतरीन व्यवस्था

रायपुर,10 जनवरी 2026। भारत स्काउट एंड गाइड के मुख्य राष्ट्रीय कमिश्नर डॉ. केके खंडेलवाल ने बालोद के ग्राम दुधली में आयोजित राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जम्बूरी में की गई व्यवस्थाओं की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने एक महीने के भीतर इतनी बेहतरीन व्यवस्था करके एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि मुझे अत्यंत गर्व के साथ यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत का प्रथम रोवर एंड रेंजर जम्बूरी का आयोजन बालोद के ग्राम दुधली में किया जा रहा है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि यह युवा शक्ति का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में देशभर से रोवर एंड रेंजर्स, ट्रेनर्स, स्काउट्स, वालंटियर्स भाग ले रहे हैं। मैंने स्वयं यहां की व्यवस्थाओं, एडवेंचर्स,भोजन व्यवस्था, टॉयलेट और प्रतिभागियों के रुकने के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। हर स्तर पर अनुशासन, सुरक्षा और उत्कृष्ट व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य भारत स्काउट गाइड का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डॉ. खण्डेलवाल ने कहा कि जम्बूरी के उद्घाटन का सुंदर आयोजन था। यह ऐतिहासिक जंबूरी है। इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने किया।

ऑनलाइन सट्टा केस...एएसआई की विभागीय जांच पर रोक

हाईकोर्ट बोला...आपराधिक केस और विभागीय जांच एक साथ नहीं चल सकती

बिलासपुर,10 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महादेव ऑनलाइन सट्टा के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि,आपराधिक केस और विभागीय जांच एक साथ नहीं चल सकती। इस आधार पर हाईकोर्ट ने रायपुर में पदस्थ एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के खिलाफ चल रही विभागीय जांच पर रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू की सिंगल बेंच में हुई। दरअसल,संतोषी नगर रायपुर निवासी चंद्रभूषण वर्मा पुलिस विभाग में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ हैं। उनके खिलाफ शिकायत मिलने के बाद रायपुर में आपराधिक केस दर्ज किया गया और कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। इसके बावजूद 26 सितंबर 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर ने उसी मामले में विभागीय आरोप पत्र जारी कर जांच शुरू कर दी। इससे क्षुब्ध होकर

एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और ऋषभदेव साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया हवाला : याचिकाकर्ता के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया। जिसमें कैप्टन एम. पॉल एन्थनी बनाम भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, स्टेन्जेन टोयोटेस्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम गिरीश, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम नीलम नाग के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब आपराधिक मामला कोर्ट में लंबित हो,तब समान आरोपों और समान गवाहों के आधार पर विभागीय जांच नहीं की जा सकती। वकीलों ने यह भी तर्क रखा कि अगर विभागीय जांच में पहले गवाहों के बयान दर्ज कर लिए जाते हैं,तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और पूरी जांच प्रक्रिया दूषित हो जाती है। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों से सहमति जताते हुए कहा कि, जब तक आपराधिक मामला लंबित है,तब तक समान आरोपों पर विभागीय जांच नहीं चल सकती। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के खिलाफ चल रही विभागीय जांच पर स्थगन (स्टे) का आदेश दे दिया।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)